गावो विश्वस्य मातरः

१६७

गोधाम

अ.भा.कृषि गोसेवा संघ
गोपुरी, वर्धा.

अनुक्रमणिका

संपादक : राधाकृष्ण बजाज, सहसंपादक : वसंत बोंबटकर

मुद्रक : रणजित् देसाई, परंधाम मुद्रणालय, पवनार जि. वर्धा, (महाराष्ट्र)

प्रकाशक : नारायण जाजू, मंत्री, अ. भा. कृषि-गोसेवा संघ, गोपुरी, वर्धा.

फोन : २८५२ तार : गोसेवा, गोपुरी, वर्धा– ४४२००१

पत्र-व्यवहार प्रकाशक के पते पर किया जाय ।

गोग्रास

वर्ष १४ : अंक ११
११ सितंबर ९०

गोपुरी, वर्धा

गोग्रास योजना : वार्षिक २० रु.
आजीवन २०० रु.

देश की अन्तरचेतना का आवाहन

[तीन महान् भारतीयों की एक पुरानी अपील, जो आज भी हमें इन्सानियत का सन्देश दे रही है ।]

आज मुल्क में जो परिस्थिति पैदा हो गयी है, वह सबके लिए गम्भीरता से सोचने का विषय है। आजादी का असली मकसद गरीबी, सामाजिक अन्याय और शोषण को खतम करने का था, पर ये बुनियादी मसले आज भी ज्यों-के-त्यों कायम हैं । बल्कि आजादी के बाद इन २२ वर्षों में कई नये मसले खडे हो गये हैं । जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हिंसा और नफरत का जोर बढा है । सारे देश के हित की दृष्टि से सोचने के बजाय भाषा, मजहब, सम्प्रदाय, जाति आदि के तंग नजरिये जगह-जगह उभड रहे हैं । यह दुर्भाग्य की बात है कि राजनैतिक दल अपने-अपने दलों के हित-साधन के लिए इस प्रकार के जज्बातों को बढावा देते हैं और इनका फायदा उठाते हैं । पिछले दिनों खास तौर से साम्प्रदायिक द्वेष और उससे पैदा होनेवाले दंगों ने देश के जीवन को जहरीला बना दिया है । धर्म के नाम पर साम्प्रदायिक झगडे करना अमानवीय कृत्य है । कोई धर्म द्वेष नहीं सिखाता । वास्तविकता यह है कि धर्म दिलों को जोडता है और समस्त मानवों का कल्याण

चाहता है। इन झगडों से देश की वर्बादी होती है, समाज में विघटन होता है और देश में निर्माण के वजाय विनाश ही विनाश होता है। आन्तरिक और वाह्य, दोनों दृष्टि से ये झगडे विनाशकारी हैं।

राजनैतिक क्षेत्र में सत्ता का जो संघर्ष चल रहा है, उससे न सिर्फ राजनैतिक अस्थिरता पैदा हुई है, वल्कि स्वयं लोकतंत्र को भी खतरा पैदा हो गया है। सवसे गम्भीर वात यह है कि इस संघर्ष के कारण सार्वजनिक जीवन में से नैतिकता और चरित्र खतम होते जा रहे हैं तथा देश की नैतिक शक्ति टूट रही है। आज की सियासत में वह ताकत नहीं है, जो इन समस्याओं का मुकावला कर सकें और देश को खतरे से वचा सकें।

इस परिस्थिति का बुनियादी इलाज लोगों की अपनी ताकत से ही सम्भव है। इस ताकत को पैदा करने के लिए लोगों में एकता, भाईचारा और संगठन जरूरी है। लोग अपने पैरों पर खडे हों, मिल-जुलकर स्वयं अपने मसले हल करने की तरफ वढें और अपने संगठन के जरिये राजनीति को भी नियंत्रित कर सकें तभी आज की समस्याओं पर काबू पाया जा सकेगा। इस काम के लिए सत्ता-निरपेक्ष निःस्वार्थ और सेवाभावी कार्यकर्ताओं की जमात आवश्यक है। आज भी देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन वे तटस्थ रहते हैं। अव समय आ गया है कि ऐसे सव लोग आज की गम्भीर परिस्थिति के मुकावले के लिए आगे आयें और जनता की ताकत वढाने के काम में अपनी निःस्वार्थ सेवाएं प्रदान करें।

(खान) अब्दुल गफ्फार (खाँ) विनोबा जयप्रकाश नारायण
सेवाग्राम : ७-११-६९
('भूदान-यज्ञ' साप्ताहिक : १७ नवम्बर १९६९ से)

राष्ट्रीय एकता के लिये दरिद्रता-निवारण

हम लोग चाहते हैं कि देश में सौमनस्य रहें, फूट न हो एवं अखंडता बनी रहें, देश में नैतिक मूल्यों का प्रसार हो, अनुशासन रहें, देश समृद्ध हो ।

इस दृष्टि से पहला कार्य दरिद्र-रेखा के नीचेवालों को उठाने का होना चाहिए। प्रधान मंत्रीजी ने संसद में घोषणा की थी कि इस देश में दरिद्र-रेखा के नीचे २३ करोड लोग हैं। दरिद्र-रेखा की सरकारी व्याख्या अब तक ६० रु. मासिक थी, अब वे प्रति व्यक्ति १२० रु. मासिक से कम आमदनीवालों को दरिद्र-रेखा के नीचे मानेंगे ।

२३ करोड लोग, याने ५ करोड परिवार। ५ व्यक्तियों के परिवार में कामवाले ३ व्यक्ति मानें, तो १५ करोड लोगों को पूरा या आंशिक काम देने की जिम्मेवारी आती है। इतने लोगों को काम देना हो, तो गांवों का कच्चा माल गांवों में ही पक्का करना होगा। हर हाथ को काम हर पेट को रोटी मिल सकेगी। गांव के पक्के माल की खपत के लिए उनके खिलाफ खडे यंत्रोद्योगों को नियंत्रित करना होगा। गांव की कमाई बरबाद न हो, इसलिये शराब बंद करनी होगी।

गांवों को सक्षम बनाने के लिये ग्राम-सभाओं को स्वशासन के अधिकार देकर उन्हें स्वयंशासित, स्वयंपूर्ण बनाना होगा। इस दिशा में पंचायत राज बिल आगे बढ रहा है। गांवों की अर्थव्यवस्था का आधार गाय-बैल हैं। गोवंश-हत्या परिपूर्ण बंद करनी होगी एवं बैल-संवर्धन की ओर विशेष ध्यान देना होगा। भारतीय कृषि और ग्राम-परिवहन, दोनों बैल-आधारित हैं। सक्षम बैल देनेवाली गो-नसलों को बढावा देने से पर्याप्त दूध भी मिलेगा और उत्तम बैल भी मिलेंगे। भैंस को बढावा देकर गो-नसल की उपेक्षा करने की आज की नीति बदलनी होगी। गोवंश-हत्या बंद होगी तो मृत चमडा गांवों में रहेगा, करोडों को रोजी मिलेगी।

रासायनिक खाद-नियंत्रण

रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं के कारण भारत की खेती दिनोंदिन कमजोर होती जा रही है। यही हालत रही तो हजारों वर्षों से

उत्पादन देनेवाली स्वर्णभूमि बंजर बन जायेगी। विश्वविख्यात वैज्ञानिक अलबर्ट आइन्स्टीन ने स्व. अमरनाथ झा के हाथों भारत के लिए संदेश भेजा था – भारत ट्रैक्टरों, उर्वरक, कीटाणुनाशक वाली यंत्रीकृत खेती-पद्धति न अपनायें। चार सौ वर्षों की खेती में ही अमरीकी जमीन की उर्वरा-शक्ति काफी हद तक समाप्त हो चली है, जबकि भारत की भूमि का उपजाऊपन कायम है, जहां कि दस हजार वर्षों से खेती होती रही है। भूमि की उर्वरा-शक्ति कायम रखने की दृष्टि से रासायनिक खादों पर परिपूर्ण नियंत्रण हो। इन खादों के कारण अन्न, जल, वायु, सबमें सूक्ष्म जहर आ गया है। मानव-जीवन खतरे में पड गया। रासायनिक खादों और ट्रैक्टरों को नियंत्रित करना होगा। इतना होगा तो बैलों को पूरा काम मिलेगा, बूढी गायों की रक्षा होगी, कंपोस्ट खाद बढेगा, भूमि की उर्वरा-शक्ति बढेगी, करोडों लोगों को अपने ही घर में काम मिलेगा।

विकास की दिशा बदलें

भारत की समृद्धि के लिये आवश्यक है कि मानव और पशु-शक्ति बढें। उससे पूरा काम लिया जाय। आज की विकास की दिशा मानव और पशुओं को बेकार करके यंत्रों को बढाने की है। परिणामस्वरूप मानव और पशु कमजोर हो रहे हैं, कॅलक्यूलेटर और काम्प्यूटर बढाते जाने से मानव का दिमाग कमजोर हो रहा है। २५-३० साल पहले तक लडकों को गणित हिसाब मुंहजबानी आते थे। स्कूल के लडके भी कॅलक्यूलेटर की मदद से जोड, बाकी, गुणाकार, भागाकार करते हैं। सृष्टि का नियम है, शरीर से काम लेंगे तो शरीर की शक्ति बढेगी, बुद्धि से काम काम लेंगे तो बुद्धि-शक्ति बढेगी। काम न लेंगे तो शक्ति घटेगी। संक्षेप में हमें विकास की दिशा बदलनी होगी। आज की विकास की दिशा विनाश की ओर ले जा रही है, यह बात पिछले ४० सालों के अनुभव से जान लेनी चाहिये।

वृक्ष-हत्या बंद हो

गोहत्या की तरह ही भारत में वृक्ष-हत्या भी बेसुमार हो रही है। वृक्ष-हत्या के कारण वर्षा का पानी कम रुकने लगा है, बाढ ज्यादा आने लगी है, भूगर्भ जल-संचय घटता जा रहा है। भूमि का कटाव बढा है। आवश्यक है कि वृक्ष-हत्या पूरी तरह रोक दी जाय। वृक्षों के संरक्षण से करोडों लोगों को काम मिलेगा, मानव को अधिक पोषण मिलेगा, पर्यावरण शुद्ध होगा, देश का

उत्पादन बढेगा, सुख-समृद्धि बढेगी। खुशी की बात है कि श्री. सुंदरलालजी बहुगुणा के प्रयास से इस दिशा में देश का ध्यान गया है, वृक्षारोपण के प्रयास भी चल रहे हैं। लेकिन अभी तक वृक्ष-हत्या बंद नहीं हुई है। एक सौ वृक्ष लगाते हैं, इतने में हजार वृक्ष कट जाते हैं। इस विनाश को सख्ती से रोकना होगा। स्थानीय सिंचाई के साधन बढाने होंगे, वर्षा का पानी अधिक से अधिक रोकने की दृष्टि से खेतों की मेड बांधना, तलाइयां बनाना, छोटे-छोटे बांध बनाना, खेतों में कंपोस्ट खाद देना, वृक्ष लगाना आदि के जरिए वर्षा का पानी रोकना होगा।

"एक ही साधे सब सधें, सब साधे सब जाय" — नीति के इस नियम के अनुसार हमारा सुझाव है कि दरिद्र-रेखा के नीचेवालों को उठाने का एक ही संकल्प किया जाय। इस संकल्प को पूरा करने के प्रयास में अन्न-वस्त्र से संबंधित केन्द्रीय उद्योगों के स्थान पर ग्रामोद्योग, शहरीकरण की जगह ग्रामों का सुदृढीकरण, श्रमशक्ति की प्रतिष्ठा, मानव और पशु-शक्ति का विकास आदि कार्य एवं सत्ता-संपत्ति का विकेंद्रीकरण सहज भाव से हो जावेंगे। भोगप्रधान पश्चिम की संस्कृति के स्थान पर त्यागप्रधान भारतीय संस्कृति के दर्शन होंगे। शिक्षा को भी इसी दिशा में मोडना होगा।

अ. भा. कृषि-गोसेवा संघ,
गोपुरी—वर्धा (महाराष्ट्र)

राधाकृष्ण बजाज
अध्यक्ष

धर्म बढता है करुणा और प्रेम से

अगर देश को बचाना है, तो गांव-गांव में ग्रामस्वराज्य स्थापित करना होगा, यही आज का धर्म है। अब केवल पूजा-पाठ करने से कोई लाभ नहीं है। उससे करुणा और दया उत्पन्न नहीं होती। पत्थर की पूजा करते करते दिल भी पत्थर बन गया है! धर्म बढता है करुणा और प्रेम से। भूदानमूलक-ग्रामोद्योग-प्रधान अहिंसक क्रान्ति का कार्य करुणा और प्रेम बढाने का कार्य है। इसलिए यह आज का धर्म है। सभी धार्मिक संस्थाओं के लोगों को चाहिए कि वे इस कार्य को उठा लें और इसके जरिये धर्म बढायें।

— विनोबा

व्यवस्था के सामने
गांधी की चुनौती गांववाले खडी करें

विमला ठकार

आज हमारे सामने चुनौती यह है कि क्या वह आवाज हम जनता के द्वारा उठवा सकते हैं ? क्या जनता यह कहेगी कि गांव-गांव में हमारे लिए एक परिश्रमालय खडा करो। जहां अम्बर चरखा हों, हथकरघे हों, चर्मोद्योग, दस्तकारी, कुम्हारी आदि के संसाधन हों, नयी-से-नयी तकनीकवाले ग्रामोपयोगी साधन हों, ये परिश्रमालय ग्राम-पंचायत की मार्फत हो या सरकार खडी करें ? इनमें पूरी मनुष्य-शक्ति तथा पशु-शक्ति का सदुपयोग हो सकें, ऐसे साधन-सम्पन्न परिश्रमालयों में हर जरूरतमंद व्यक्ति दिन के सात-आठ घण्टे काम करके रोजी-रोटी कमा सकें। रोजी-रोटी कमाने के लिए लोगों को अपना गाँव, अपनी जमीन न छोडनी पडें।

गांव की जनता यह कहें कि "हमारे गांव को एक-दो एकड जमीन ऐसी मिलें, जहाँ हम आयुर्वेदिक औषधियां उगा लें, गायों के लिए चारा उगा लें, हमारे लगाये हुए पेडों को सरकारी अधिकारी काट न सकें।" यह मांग ग्रामजनों के मुख से – उस "सहस्रशीर्षा पुरुष" के मुख से – निकलनी चाहिए। केवल हमारे नारों, जुलूसों, प्रदर्शनों से या दिल्ली जाकर धरना देने मात्र से कोई काम होनेवाला नहीं। काम तभी होगा, यदि भारत के कोने से आवाज उठा सकें – खादी-ग्रामोद्योग के कार्यकर्ता, ग्रामदान-ग्रामनिर्माण का काम किये हुए कार्यकर्ता, जो सर्वोदय का विचार और ग्राम-स्वराज्य का चिन्तन देते रहे हैं, वे लोग और जो प्रबुद्धजन हैं, जिन्होंने तीसरी लहर को भी देख लिया है, औद्योगिक क्रान्ति के बाद की बात और दुनिया की स्थिति जो देख रहे हैं, गोर्बाचेव-जैसे को रूस में बैठकर विकेंद्रीकरण की बात करनी पडती है, यह जिन्होंने देखा है, उन सब लोगों को इकट्ठे होकर ग्रामजनों के मुख से यह मांग खडी करनी चाहिए।

ग्रामजनों को समझाना होगा कि भीख के लिए हाथ पसारना, अपमानित होना, और दिये हुए भीख के टुकडे के सहारे, या अनुदानों के सहारे खादी-ग्रामोद्योग चलाते रहना इसमें गौरव, गरिमा नहीं है। इच्छा होने पर भी

"काम का अधिकार" क्यों अमल में नहीं लाया जा सकेगा, उन कारणों का निराकरण गांधीजीवन-दर्शन में हमें मिल जायेगा।

अतः मित्रो! केवल ग्रामोत्थान की बात नहीं, केवल गाय को बचाने के कानून से गाय बच पायेगी या नहीं, कहा नहीं जा सकता। देश की पूरी विकास-नीति पर अब गांधी-जीवन-दर्शन एवं गांधी-दृष्टि का एक नैतिक आक्रमण करना होगा। शहरों में विचार-संचार द्वारा एक नैतिक बल खडा किया जाय, और गांवों में आत्मविश्वास पनपाया जाय। पंचायती राज ग्राम-स्वराज्य की दिशा और जगह ले सकता है या नहीं, यह सोचना है।

गांववाले पंचायती राज को कैसे संभालें? यदि गांव को रेवेन्यू का अधिकार दिया जाता है, गांव की विधायिका बनती है, तो उन्हें जो अधिकार दिये जाये, उन पर अमल करने की शक्ति और आत्मविश्वास ग्रामजनों में हम जगायें और वे कहें कि वह पर्याप्त नहीं। कठिनाई यह है कि केन्द्रीकरण की दृढ पकडवाली शक्तियों से लडना पडेगा।

हम अपना आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, प्रशासन खुद चलायेंगे, इसलिए ग्राम-प्रशासन के द्वारा ग्रामस्वराज्य और आर्थिक स्वावलंबन के द्वारा ग्रामस्वराज्य, इन दोनों की मांग ग्रामजनों में करनी हैं।

गांधीजनों की कसौटी की घडी

हमारे साथ नया खून कम है। और फिर हम संस्थानिष्ठ बन चुके हैं, संस्थाओं के कलेवर हमें सम्भालने हैं। उसमें कितनी ही तकनीकी दिक्कतें और मर्यादायें आ जाती हैं। लेकिन हां, आज भी यह हकीकत जरूर है कि भारतीय जनता की जडों तक जितनी हमारी पहुंच रही है, उतनी अन्य किसीकी नहीं, न किसी राजनैतिक पक्ष की, न किसी संस्था-संगठन की। यह बापू का, विनोबाजी का आशीर्वाद है, वरदान है कि अपनी बहुत बडी विरासत है। गांव-गांव में कतिने हैं, बुनकर हैं। भूदान-ग्रामदान की बात जहां-जहां गयी उन गांवों में आज भी उस जमाने के लोग जीवित हैं और याद रखे हुए हैं। दिल-दिमाग हाथ-पांव से टूटे हुए गांवों में भी अभी बहुत ताकत बची हुई हैं, उस भग्नावस्था में बैठे हुए दिल अभी भी हमसे अधिक शक्तिशाली हैं। जरूरत है, उनका आत्मविश्वास जगाने की, उनके संगठन के पीछे नैतिक बल देने की, उनके साथ खडे होने की। उतना करने के लिए यदि हमारी मानसिक तैयारी है, बौद्धिक तैयारी है और अपने जीवन की तत्परता है तो निराश होने का कारण नहीं है। यह कसौटी की घडी है, निराशा की घडी नहीं है।

अपनी श्रद्धा को घिसने की यह घडी है, यदि उस पर कुछ धूल चढी हो तो वह धूल झाड देने का यह मुहूर्त है। २१ वीं शताब्दी गांधी-विचार की होगी, लेकिन बीच में जो दस साल खडे हैं, उनमें हमें क्या करना है? काम में लगना हैं तो आज ही लगना है। गांधी-विचार और जीवन-दर्शन में शक्ति है, और दुनिया उनकी ओर आ रही है यह सच है। पर सवाल दुनिया का नहीं अपना है, इस देश का सवाल है। चुनौती का स्वीकार करने और उससे जुझने के लिए ये चार-पांच ही वर्ष तो हैं। ज्यादा समय नहीं है।

पहले तीन-चार विकल्पों के साथ यह पांचवाँ विकल्प है। उसके अल्प प्रयोग हुए हैं। इन लूले-लँगडे प्रयोगों का अनुभव भी जो बताता है, वह पर्याप्त है। खादी-ग्रामोद्योगों के द्वारा रोजगार देने की सम्भावना की दृष्टि से, मनुष्य की शक्ति बढाने की दृष्टि से, गांवों को सुरक्षित रखने की दृष्टि से हमारे-आपके पास जो नतीजे हैं, वे सरकारी योजनाओं के द्वारा चालीस साल में भी नहीं मिले हैं। उसमें गरीबी घटाने, अमीरी बढाने की बात थी, यहां रोजी-रोटी दिलाने की बात है। तथाकथित वैभव एवं समृद्धि की बात आज इनमें नहीं की जा सकती, लेकिन भुखमरी हटाने की शक्ति इसमें है, और मानव को न्यूनतम स्तर पर से मानवीय स्तर पर लाने की सम्भावना है। इसमें गांव उजाडकर शहरों में, झुग्गी-झोपडियों में व्यवस्था कराने और आखिर बरबाद होने की बात नहीं। मानव से निचले स्तर से उठाकर मनुष्यों की जिन्दगी को मानवीय स्तर पर लाने के लिए सम्मान व स्वाभिमान के साथ दो जून की इज्जतभरी रोटी दी जा सके तो वह आपके स्वचालित यंत्रीकरण के द्वारा वैभव बढाने जैसी बडी-बडी बातों से बढकर है। यह 'स्वराज्य' की बात है, वह 'पर राज्य' की बात है, यह स्वाधीनता की बात है, वह पराधीमता की बात है।

इससिए गांधी-परिवार के अपने तपे-तपाये साथी-मित्रों से हाथ जोडकर इतना ही कहना है कि संगठित होने भर की देर है। संगठित-सुग्रथित पुरुषार्थ की जरूरत है। यदि आज एक व्यक्ति कुछ करता है, कल दूसरा उसे उठाकर कुछ और करता है और परसों तीसरा आकर अपनी बात करना-कराना चाहता है, तो शक्ति का अपव्यय होता है, परिणाम वांछित नहीं आता। यदि सबकी संगठित शक्ति लग जाय तो उचित परिणाम की सम्भावना, अनिष्ट हटने की सम्भावना तो खडी ही हो जाती है। वह संगठित होने की प्रेरणा हम सबमें जागे, यह प्रभु से प्रार्थना है। (प्रस्तुति: डा० उर्मिला शर्मा)

गांधी की चेतावनी

• ॐ पूर्ण स्वतंत्र •

गांधी-समाज ने गांधी की चुनौती स्वीकार की है और संपूर्ण भारत राष्ट्र को इस चुनौती को स्वीकार कराने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस महान संकल्प के लिए बधाई ! समय अनुकूल है, परिवर्तन की हवा बडी तेजी से चल रही है। विश्व में पूंजीवादी और साम्यवादी, दोनों व्यवस्थाएं मानव-कल्याण में असफल हो चुकी है और दुनियां तीसरे विकल्प की खोज में है, जो गांधी के पास है। स्वयं अपने देश में भी पिछले दिनों सत्ता-परिवर्तन के बाद परिस्थिति अनुकूल बनी है। पिछले लगभग ४० वर्षों से जो स्वराज्य दिल्ली के खूंटे से बंधा हुआ था, गांवों की ओर बढने लगा हैं, भारत की धरती पर उतर कर प्रतिष्ठित होने के लिये अभिमुखता जगी है, सही दिशा में चिंतन शुरू हुआ है, अनुकूल माहौल बना है। अत: कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि "गांधी" का बीज बोने के लिए मौसम और खेत, दोनों तैयार हैं।

किंतु सर्वप्रथम हमको निर्णय यह करना होगा कि गांधी क्या है : क्या गांधी एक विचार है, राष्ट्र के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक विकास का एक दर्शन है, जो विश्व के लिए 'समग्र दर्शन' के रूप में विकसित हुआ है ? अथवा गांधी एक जीवन-पद्धति है, सत्य की निरंतर चलनेवाली एक खोज है, अंतरात्मा की प्रयोग-शाला में आध्यात्मिक जगत के उच्च से उच्चतर सत्य का अनुसंधान है, जिसकी उपलब्धि भौतिक जगत के विभिन्न क्षेत्रों — राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आदि – में लागू होकर मानव समाज को जीवन का एक नया आयाम, संघर्ष की आदिकालीन समस्या का स्थाई समाधान देने का एक निरंतर प्रयत्न है ? मेरी दृष्टि में गांधी एक 'समग्र पुरुष' है, जीवन की एक समग्र इकाई है। आत्म-साधना के मौन में उसकी जडें आंतर-जगत में जितनी गहरी जाती हैं, उसकी शाखाएं बाह्य जगत के कर्म-क्षेत्र में उतनी ही दूर तक फैल जाती हैं और ऊंचे उठ जाती हैं। यही उनकी अक्षय शक्ति और युगांतरकारी प्रभावशालीनता का रहस्य है। गांधी एक 'जीवन-वैज्ञानिक' है जिसने अपने उदाहरण के द्वारा जीवन के वैज्ञानिक स्वरूप का प्रस्तुतीकरण किया है।

लेकिन पिछले ४० वर्ष का अनुभव बताता है कि हम गांधी की जीवन-पद्धति का अनुसरण करने में असफल रहे हैं। हमने उनकी विचारधारा को तो ग्रहण कर लिया, किंतु उस आंतरिक स्रोत को अपने अंदर खोलने में असमर्थ रहे जहां से उनकी विचारधारा को व्यावहारिक कर्म में परिणित करने की शक्ति आती थी। अतः इस आंतरिक शक्ति के अभाव में न तो गुणात्मक दृष्टि से हमारा जीवन उनकी श्रेणी का बन सका और न ही हम व्यावहारिक रूप में उस कर्म को कर सके जो उनकी विचारधारा में निर्दिष्ट है; -- यह आंतर 'चेतना-शक्ति' ही जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाती है जो उसके स्वरूप को आध्यात्मिकता और उसके व्यवहार को नैतिकता प्रदान करती है। आंतरिक जीवन में जागृत न हो पाने के कारण बाहरी कर्म में भी सफल नहीं हो सके। यहां इतना और जोड देना भी प्रासंगिक रहेगा कि यह 'दुर्घटना' केवल हमारे ही साथ हुई हो ऐसी बात नहीं है। यह संपूर्ण मानव-इतिहास की कहानी है, हर महापुरुष के बाद यह दोहराई गई है। उस महापुरुष के शब्द और शरीर नाम, रूप को तो हमने सुरक्षित रखा है, किंतु उसका सत्य और आत्मा हमारे हाथों से फिसल गई है। जीवन-गंगा को फोटोग्राफ में नहीं समेटा जा सकता, उसको तो जीवन में ही धारण किया जा सकता है। यह मानव-इतिहास की असफलता है। किंतु समय इतना आगे बढ गया है और जीवन ऐसे नाज़ुक बिंदु पर पहुंच गया है कि वह इस 'असफलता' को अब बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अगर हम सृजनात्मक जीवन की अजस्र धारा का अवरुद्ध प्रवाह नहीं खोल सके, 'स्रोत' को उन्मुक्त नहीं कर सके तो जीवन नष्ट हो जायेगा, तीसरा कोई विकल्प है नहीं।

अतः हम गांधीजनों के सामने आज सचमुच एक ऐतिहासिक चुनौती है; गांधी की जीवन-पद्धति को अपने जीवन में धारण करके केवल भारत राष्ट्र के लिए ही नहीं, अपितु संपूर्ण मानव जगत के लिए मृत्यु के मुख से मुक्त होने का द्वार खोलना। वस्तुतः यह है 'गांधी की चुनौती'। लेकिन अभियान की जो योजना प्रस्तुत की गई है, उसमें इसकी स्वीकृति का कहीं आभास नहीं मिलता। वहां केवल विचारधारा के प्रचार-प्रसार का ही कार्यक्रम पेश किया गया है। आध्यात्मिक सत्य, नैतिक मूल्यों, जीवन के गुणात्मक परिवर्तन हेतु किसी अभि-क्रम का कोई संकेत नहीं है। जीवन की जड को पानी दिये बिना पेड पर फूल

कहां से आयेगा ? यही तो भूल है, जो हम ४० वर्षों से किये चले जा रहे हैं और मानव सदियों से करता आ रहा है। इससे शंका पैदा होती है कि हम 'गांधी' की चुनौती को समझ भी पा रहे हैं अथवा नहीं। अतः मेरी भाइयों, साथियों, मित्रों से हाथ जोडकर प्रार्थना है कि गांधी की देन और युग की मांग को अपनी अंतरात्मा की गहराई में जाकर पहचाने क्योंकि इन दोनों का स्रोत वहीं है।

पूंजीवादी और साम्यवादी दो विचारधाराएं थी, जो जीवन के परिमाणात्मक विकास को दृष्टिगत रखकर चलती थी —— वे संपूर्ण जीवन को अपने में नहीं समेटती थी, इसीलिये असफल हो गई। किंतु 'गांधी' कोई विचारधारा नहीं है, गांधी संपूर्ण जीवन का नाम है। जीवन का विकास अंदर की जड की ओर होता है, बाहर तो उसकी अभिव्यक्ति होती है, —— या कह लीजिए कि मूल से चहुं ओर होता है, अगर चहुं ओर (समय) नहीं होता तो जीवन-विकास हो ही नहीं सकता है। यह जीवन-विज्ञान का अकाट्य विधान है। अतः यदि हम मूल को छोडकर चलेंगे —— जैसा कि अभी हम व्यापारिक रूप में कर रहे हैं, तो न तो हम गांधी की चुनौती को स्वीकार कर पायेंगे और न ही दुनिया को पूंजीवाद-साम्यवाद का विकल्प दे पायेंगे, जिसकी आज अनिवार्य आवश्यकता है, मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए।

गांधी से जीवन-सूत्र के रूप में हमारे पास एक ऐतिहासिक धरोहर है, मानव जाति का अस्तित्व संकट में है और गांधी-पुत्रों के रूप में इस सूत्र का प्रयोग करके मानव जीवन की रक्षा करने का दायित्व हमारे ऊपर है। अगर इस दायित्व की पूर्ति में हम असफल रहे तो इतिहास कभी हमें क्षमा नहीं करेगा। यह 'गांधी की चेतावनी' है। अतः गांधी-परिवार से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि स्थिति की गंभीरता और ऐतिहासिक महत्त्व को पहचानते हुए और अपने केंद्रीय दायित्व का अहसास करते हुए हम केवल गांधी-विचार के प्रचार-प्रसार तक सीमित न रहकर (क्योंकि इतने मात्र से न तो हम अपने दायित्व की ही पूर्ति कर पायेंगे और न ही इच्छित लक्ष्य की सिद्धि करने में सफल हो पायेंगे!); "गांधी-जीवन-पद्धति" को विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करने का सृजनात्मक, क्रांतिकारी अभियान शुरू करें। हम लोगों को, विशेषकर युवकों को केवल इतना ही नहीं बतायें कि गांधी ने क्या कहा था, बल्कि यह भी कि

उसने क्या किया था और जो कुछ किया था उसको करने की शक्ति कहां से आई थी और वही शक्ति हमारे अंदर कैसे आ सकती हैं ? यह केवल बतायें नहीं, बल्कि उस शक्ति को उनके अंदर से 'जागृत' करने का कुछ अभिक्रम भी करें। यहां से जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आयेगा। और वर्तमान परिस्थिति में जब हम इस परिवर्तन की अनिवार्यता को अनुभव कर लेंगे तो इसका आरंभ हमारे स्वयं के अंदर से होगा। इससे न केवल हम गांधी के स्वप्नों के भारत का निर्माण कर पायेंगे, बल्कि आज अंधकार में भटकती किंतु जीवन के छट-पटाती मानवता के लिए अभिनव जीवन का स्वर्णिम द्वार भी खोल पायेंगे। मुझे विश्वास है कि बापू के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से हम इस चुनौती को स्वीकार करने में सफल होंगे।

जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आने के बाद ही समाज में व्यवस्था-परिवर्तन आ सकता है। और गुणात्मक परिवर्तन के लिए हमें आरंभ 'व्यक्ति' से करना होगा, क्योंकि जीवन की मूल इकाई व्यक्ति है, गांव या परिवार समाज की इकाई हैं। अत: मौलिक-परिवर्तन-अभियान का आरंभ हमें मौलिक इकाई, व्यक्ति (मनुष्य) से ही करना होगा। मूल से आरंभ किया निर्माण ही शिखर (पूर्णता) तक पहुंच सकता हैं !

उत्पादन में आध्यात्मिक आनन्द

"अत्यन्त सूक्ष्म श्रम श्रम-विभाजन करके मनुष्य को जड यंत्र जैसा बना देकर चार-छ: घण्टे की नीरस क्रिया में उसे जोतना और फिर मौज शौक के लिए छोड देना, इससे मनुजाति का कल्याण न होगा। बल्कि उद्योग-धन्धों की व्यवस्था के ऐसे रास्ते ढूंढने चाहिए जिनसे उसे अपने करने के काम में ही आनन्द आये, वही उनके शौक की चीज बन जाये और उसी में वह अपना आध्यात्मिक विकास भी कर सके।

— महात्मा गांधी

आठवीं पंचवर्षीय योजना में कतलखानों की भरमार

विदेशी मुद्रा कमाने के लोभ में भारत सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित कतलखानों को निर्माण करने की योजना बनाई है, जिससे वे १९८९-९० में निर्यात किये गये ११० करोड रुपयों के मांस के स्थान पर ५०० करोड रुपयों का मांस प्रति वर्ष निर्यात कर सके।

(क) कतलखानों का निर्माण

१. श्रीनगर
२. माझीतर (सिक्कीम)
३. काचरनकानहल्ली (बेंगलोर)
४. हैदराबाद
५. दिल्ली
६. मंगलगिरि (गुंटुर)
७. विशाखापट्टनम (आंध्र)
८. रूद्रारम (आंध्र)

(ख) वर्तमान कतलखानों में सुधार

१. इलाहाबाद
२. वाराणसी
३. अलीगढ
४. जलंधर
५. पुणे
६. बजबज (बंगाल)
७. सईदापेट (मद्रास)
८. पेराम्बुर (मद्रास)
९. वडी-दमन
१०. बडा दीव
११. चंडीगढ

(ग) पक्षियों द्वारा नुकसान पहुँचाने के नाम पर रक्षा मंत्रालय ने निम्न स्थानों पर नये कतलखानों को लगाने की योजना बनायी है :—

१. ग्वालियर
२. गोरखपुर
३. जोधपुर
४. डिंडीगल
५. तेजपुर
६. चबुआ
७. सिरसा
८. श्रीनगर
९. जम्मू
१०. कलाईकुंडा
११. हैदराबाद
१२. त्रिवेन्द्रम
१३. बेंगलोर
१४. पटना
१५. नागपुर
१६. कलकत्ता
१७. मद्रास
१८. बंबई
१९. दिल्ली
२०. हिन्दन (Hindan)
२१. आगरा
२२. अम्बाला

देश के प्रबुद्ध व्यक्तियों, संस्थाओं एवं जनता से अपील एवं आग्रह है कि वे सरकार की इस आत्मघाती नीतियों का डटकर विरोध करें, जिससे देश का पशुधन विदेशी मुद्रा के लोभ में समाप्त न हो जाय एवं हम अपनी भावी पीढी के लिये अंधकारमय भविष्य न छोड जायें। ('अहिंसा विहंगम' से)

भारत में ऐसे भी मंत्री हैं.!

— वसंत बोंबटकर

कर्नाटक के कृषि-पशुपालन मंत्री श्री. वसवलिंगप्पाजी ने काचरनकॉनहल्ली (वेंगलोर) में अत्याधुनिक कतलखाने की आवश्यकता वताते हुए कहा कि दस लाख पशुओं में से नौ लाख पशुओं को हटाये जाने से वचे एक लाख पशुओं को भरपेट खाना मिलेगा। इसी सोच से कूडा-कचरा समझकर ९० प्रतिशत पशुओं को कतल करने के लिए कर्नाटक में आधुनिक संयंत्र लगाकर कार-खाने खोले जा रहे हैं।

भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्री को अब्र राहत की सांस लेनी चाहिए कि इसी भारत के कर्नाटक प्रदेश के प्रतिभाशाली कृषि मंत्री श्री. बसव-लिंगप्पा ने समस्या सुलझाने का एक आसान तरीका ईजाद किया है। इस देश में आबादी बढने से २३ करोड लोग गरीबी-रेखा के नीचे जी रहे हैं। यहां की ८६ करोड आबादी से इन २३ करोड लोगों को हटा दें, तो बचे ६३ करोड लोगों को अधिक चीजें मुहय्या होगी। और इनमें से अमीरी-रेखा में आनेवाले पांच-छह करोड और लोग हटा दें, तो उनकी साधन-संपत्ति बचे ५६ करोड लोगों को प्राप्त होने से उनकी स्थिति और बेहतर हो जायेंगी !

मानव संसाधन मंत्री आगे आनेवाले दिनों में गरीबी-भूखमरी-बेरोजगारी, निरक्षरता से भारतीय नागरिक को मुक्त करना चाहते हैं, तो उन्हें बसव-लिंगप्पाजी के फार्मूले में थोडा संशोधन करके गरीबी-रेखा के नीचे के सभी लोगों की तुरंत कानूनन नसवंदी करानी चाहिए !

यह पढकर आप क्यों चौंक गए ? क्या इसमें कहीं आपका नंबर लगने का खतरा आपको दिखता है ? या इसे अमानुषी जानकर आपके हृदय को ठेंस पहुंची हो, तो आपकी जिंदादिली का वह सबूत है। आपके इस जिंदादिली का एहसान मानकर मैं आपसे अनुनय करता हूं कि मानव के बारे में आपने जो

कर्तव्य-भावना का परिचय दिया, क्या बहुगुणी-बहुकामी पशुओं के प्रति भी हमारा कोई कर्तव्य नहीं है ? क्या वे मूक हैं, बोल नहीं सकते, संगठन नहीं बना सकते, उनकी इस कमी का अनुचित लाभ उठाकर उनकी जान पर हम उतर आये ?

जो पशु आपको दूध देता है, जोत और ढुलाई का काम करता है, अपने गोबर से, खाद, जलावन, प्रकाश (गॅसप्लॅंट द्वारा) देता है, कीटनाशक मूत्र दें, पैरों के संरक्षण लिए चमडा और खाद और अन्य औद्योगिक उत्पादनों के लिये हड्डी, चरबी, मांस, खून दें, ऐसे यह संपत्ति के निरंतर बहनेवाले इस झरने को ९०% खतम करने में कोई बुद्धिमानी हैं ? कृतज्ञता का, इन्सानियत का क्या यही तरीका है ?

मान लें कि बसवलिंगप्पाजी ने ९०% पशु कटवा दिये तो एक ही पशु-द्वारा होनेवाले इतने सारे कार्य, क्या किसी एक यंत्र द्वारा किये जा सकते हैं ? ट्रैक्टर, खाद और कीटनाशक दवाइयों के कारखाने उनकी जगह लेने के लिये अलग-अलग चलायें, तो क्या इतनी पूंजी और साधन हमारे पास हैं ? पशु निरंतर उगनेवाले घासपात पर जीते हैं, दुनिया में से चंद दिनों में समाप्त होनेवाले डिझेल, पेट्रोल के बल पर चलनेवाले इन यंत्रों को काम में लें तो कितने दिन यह व्यवस्था चलेगी ? बीच में खाडी देशों में चल रही गडबड या पडोसी से युद्ध छिड जाय तो पेट्रोल, डिझेल की सप्लाय की क्या स्थिति रहेगी ? उस हालत में पशु के बजाय यंत्रों पर निर्भर यह खेती ठप्प होगी और उससे जो अकाल, बेरोजगारी फैलेगी । उस महासंकट को क्या भारत झेल सकेगा ? यह यंत्र प्रदूषण बढाते हैं, रासायनिक खाद और कीटनाशक जमीन को कमजोर और जहरीला बनाते हैं, जिससे हवा, पानी, अनाज, सबमें प्रदूषण की मात्रा बढती है । इस नुकसान की क्या कभी पूर्ति हो सकती है ?

पशु भारत के लिए अनिवार्य है । भारत की आज की कृषि को व्यवस्थित ढंग से करने के लिये दस करोड बैलों की आवश्यकता है और आज केवल सात करोड बैल बचे हैं । हर साल सवा करोड बैल काटे जा रहे हैं, जिनमें आधी संख्या तो अच्छे बैलों की है । भारत में पशु ज्यादा हैं, यह भी एक वहम है । कृषि मंत्री का यह बयान सरासर गलत और झूठ है ।

नीचे की तालिका से वह साबित होता है –

एक हजार मनुष्यों के अनुपात में पशु-संख्या

	भारत	अर्जेंटिना	आस्ट्रिया	कोलंबिया	ब्राजील
गायबैल	२७८	२०८९	१३६५	९१७	७२८

	भारत	नेपाल	पाकिस्तान	थायलैंड	वियतनाम
भैंस	१००	२८४	१३०	१२५	४०३

	भारत	सुडान	पाकिस्तान	इथोपिया	टर्की	सोमानिया
बकरे	११८	६७७	३८७	५२३	३७८	३२६४

	भारत	न्युझिलैंड	अर्जेंटिना	उरुग्वे	द. आफ्रिका
भेड	६२	२३५२८	१०८३	७६७१	१०२२

इन आंकडों से पता चलता है कि भारत में फी आदमी पशुसंख्या कम है। और बैलों की कमी है। यहां तक कि भारत का कल तक का हिस्सा, पाकिसतन की तुलना में भी भारत में पशुओं की संख्या कम है।

१९१७ में रूस में कम्युनिस्ट क्रांति ने खेती-पशुओं का राष्ट्रीयकरण करने की नीति चलाई। तब किसानों ने सरकार को पशु सौंपने के बजाय काफी मात्रा में काटकर उन्हें खा गये, और पशुओं का भीषण अकाल होने से आज ७३ साल के बाद भी वह राष्ट्र अनाज और चमडे के लिए मोहताज है।

तो निरंतर संपत्ति का यह बहता स्रोत भारत में समाप्त किया गया तो भारत की भूमि, गांव, किसान और समूचा देश अकथनीय संकटों से घिर जायेगा। एक बार पेट्रो डॉलर के लिये पशु समाप्त कर दिये तो दुबारा वे कहां से प्राप्त होंगे? और उनकी जगह लेनेवाले इन नये और ज्यादा बढ गये यंत्रों के डिजेल, पेट्रोल की बढती मांग की पूर्ति कैसे होगी?

कर्नाटक के कृषि मंत्री और पाश्चात्य अर्थशास्त्र पढे-लिखे हमारे योजनाकार और अफसरों के भारत की वास्तविकता के बारे में अज्ञान के कारण ही, और भोगवादी विकृति के कारण जंगल नष्ट हो गये, नदियां सूख रही हैं और जो बहती हैं, वे भी पेयजल के लायक नहीं रखी हैं। जमीन, हवा, पानी, अनाज,

फल, दूध में प्रदूषण बढ रहा है, गलत शिक्षा-नीति से नौजवान बेरोजगार, बेकार, व्यसनी बन गये हैं, करोडों लोगों को गांवों में अपना घरबार छोडकर शहरों में फूटपाथ पर या गंदी झुग्गी-झोपडी में लाकर पटक दिया है। भ्रष्टाचार से नैतिकता समाप्त है। अब यही अकलमंद लोग बहुकामी पशु को खतम करके घर में कुत्ते और जंगलों में शेर पालने लगे हैं! इनकी अब इसके आगे यही हरकतें चलने दी, तो ये नाम के भारतीय, लेकिन विचार से अभारतीय, इस देश को बरबाद और संपन्न देशों को गुलाम बनाकर छोडेंगे।

कॉंग्रेस ने अपने जन्मकाल से गोवंश-हत्या बंदी का आश्वासन भारतवासियों को दिया है। कॉंग्रेस के पूर्व प्रधान मंत्रियों ने पार्लमेंट में गोवंश की कतल को रोकने का आश्वासन दिया हुआ है। १९६९ तक कॉंग्रेसजनों ने बैलजोडी और गाय-बछडे के चुनाव-चिन्ह पर गांव के लोगों से वोट प्राप्त किये हैं, क्या उनके प्रति यह धोखाधडी नहीं है? भारत के संविधान ने पशुसंवर्धन का निर्देश दिया है। श्री. बसवलिंगप्पा कॉंग्रेस के सदस्य के नाते इन निर्णयों से बंधे हैं, मंत्रीपद की शपथ ग्रहण करते समय उन्होंने संविधान के संरक्षण का वचन राष्ट्र को दिया है। इस नाते वे दोनों ओर से ९०% पशु हटाने के लिए कतल के कारखाने की योजना अमल में लाते हैं, तो दोहरा अपराध करते हैं। मतदाता और नागरिक इस बात की खबर लें।

★ ★
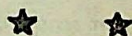
यंत्रों का नियंत्रण : एक चेतावनी

यदि पूर्वी देश भी मशीनों और तकनीक के प्रति आकर्षित होकर पश्चिमी राष्ट्रों की तरह उनका उपयोग विशाल औद्योगिक संस्थानों या सैनिक प्रतिष्ठानों की स्थापना में करने लगेंगे तो वे शक्ति की राजनीति में उलझकर मृत्यु का खतरा मोल ले लेंगे। मशीनों का प्रभुत्व स्थापित हो गया तो हमारी सम्पूर्ण प्रगति व्यर्थ हो जायेगी। मानवीय नियन्त्रण से मुक्त हो जाने पर टेक्नालॉजी अपना अर्थ खो बैठती है और साध्य पर साधन की विजय हो जाती है। ऊंचे रहनसहन के लिए उत्सुक इस युग में हम सरल और पवित्र जीवन के अनिवार्य मूल्य को नजरअन्दाज कर रहे हैं।

— डॉ. एस. राधाकृष्णन्

लन्दन की मस्जिद के प्रसिद्ध इमाम द्वारा शाकाहारी बनने की अपील

किसी भी धर्म-ग्रंथ में मांस खाने की शिक्षा नहीं

— बशीर अहमद मसेरी

लन्दन की मस्जिद के श्रद्धेय इमाम अल-हफिज बशीर अहमद मसेरी ने भारत, पाकिस्तान और बंगला देश के मुसलमानों से शाकाहारी बनने की अपील की है। वे स्वयं शाकाहारी हैं और लोगों को शाकाहारी बनने की प्रेरणा देते हैं। उनका कहना है कि किसी भी धर्म-ग्रन्थ में मांस खाने की शिक्षा नहीं दी है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक – "इस्लामिक कन्सर्न फॉर ॲनीमल" – में इस्लाम धर्म के अनुसार ऐसे उदाहरण दिये हैं, जो मनुष्य को जानवरों के प्रति दयालु होने की शिक्षा देते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान भाई इस विषय में शिक्षा-भ्रमित हैं। जो लोग जानवरों पर अत्याचार करते हैं, वे मानवता के विपरीत हैं और पर्यावरण के लिये घातक राह पर चल रहे हैं। उन्होंने भारत, पाकिस्तान और बंगला देश में स्थान-स्थान पर जाकर यह संदेश लोगों तक पहुंचाने का बीडा उठाया है। वे चाहते हैं कि इस्लाम के नाम पर पशुओं की हत्या करना और मांस खाना सर्वथा अनुचित है। जब उन्होंने जानवरों पर होनेवाले अत्याचारों की मुस्लिम धर्म के अनुसार मनाही के बारे में पुस्तक लिखना प्रारंभ किया, तो उनके बहुतसे दोस्त आश्चर्य में पड गये तथा उन्होंने सलाह दी कि मुसलमानों के सामने बहुतसी अन्य समस्याएं हैं, उन्हें हल करने की पहल करें।

मसेरी साहब का दृष्टिकोण है कि इस दुनिया में जीवित प्राणी एक-दूसरे का शोषण न करें। मनुष्य जानवरों का उपयोग करें, उससे मानव जाति का भला होता है। परन्तु जानवरों की हत्या का कारण नहीं होना चाहिये। मानव जाति की समस्याएं चाहें वे शारीरिक हों या आध्यात्मिक हों, वे सब मनुष्य की बनाई हुई समस्याएं हैं। जानवर कभी भी मनुष्य को जानबुझकर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तब मनुष्य ही अपने स्वार्थ के लिए इन जानवरों पर अत्याचार क्यों करते हैं ? आध्यात्मिक दृष्टि से बलिप्रथा का कोई औचित्य नहीं है। फिर भी लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बलि चढाते हैं। उन्होंने

इस्लाम धर्म के अनुसार जानवरों के अधिकारों के बारे में उनके साथ मनुष्य के बर्ताव के वारे में स्पष्ट किया है, उनका दावा है कि मुस्लीम धर्म के अनुसार अन्य कहीं से इस विषय पर राय लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना आवश्यक है कि जो मस्तिष्क में गलत धारणाएं बनी हुई हैं उन्हें हटाएं। अध्यात्म के कर्मकाण्डों से वंचित रहने की भी सलाह दी है। मौलाना मसेरी एक पढेलिखे मुसलमान हैं, जिन्हें हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी और अरबी भाषा का अच्छा ज्ञान है। उन्हें पवित्र कुरान कंठस्थ है और सर्वप्रथम शाहजहां मस्जिद दून के प्रथम इमाम नियुक्त हुए। जानवरों के प्रति उनके हृदय में बहुत दर्द है। उनकी आत्मा की पुकार है कि मुसलमान भाइयों को उनकी बात हृदय में उतारनी चाहिए। मसेरी साहब की उम्र ७५ वर्ष की है, परन्तु उनका स्वास्थ्य ५० वर्ष के एक कर्मठ व्यक्ति जैसा लगता है।

दिनांक ११ फरवरी, १९९० को भारतीय पशु-कल्याण संस्थान (एनिमल वेलफेअर एसोसिएशन ऑफ इंडिया) ने मौलाना मसेरी साहब का हार्दिक स्वागत किया और उनसे प्रार्थना की कि वे इस संदेश का संयुक्त राष्ट्रसंघ तक पहुंचाने में मदद करें। मानव-अधिकारों की तरह जानवरों को भी कुछ मौलिक अधिकार दिये जावें। भारतीय पशु-कल्याण संस्थान के सभी सदस्यों ने यह बात स्पष्ट रूप से कही कि भारतवासी यांत्रिक और आधुनिक बूचडखानों का विरोध इसलिए करते हैं कि इससे पशुओं की अधिक हत्या होगी, मांस का अधिक उत्पादन होगा, जिससे सारे देश में मांसाहार को बढावा मिलेगा और पशुओं की हत्याओं में वृद्धि होगी। उन्होंने पूर्व भारतीय पशु-कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रो. रामस्वामी के वक्तव्यों की कडी आलोचना की और स्पष्ट रूप से कहा कि प्रो. रामस्वामी का दृष्टिकोण सर्वथा अनुचित था। मांस का निर्यात करने के लिये बूचडखानों का नवीनीकरण पशुओं के साथ धोखा देना होगा और भारत की आर्थिक निर्भरता के लिये घातक होगा। यह एक ऐसा मूर्खतापूर्ण कदम होगा, जो आगामी समय में पशु-कल्याण के सभी रास्ते बंद कर देगा।
.('अर्हंत जैन टाइम्स' जुलाई के सौजन्य से)

प्रस्तुति : मानव मुनि

जैविक कीटनाशक का उपयोग करें

भारतवर्ष में लगभग दो लाख टन कीटनाशक दवाइयों का उपयोग होता है, जिसमें कृषकों को काफी व्यय करना पडता है। साथ ही, कीटनाशक दवाइयों के उपयोग से वातावरण भी प्रदूषित होता है, जिसका सीधा प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर पडता है। दस वर्षों के दौरान प्रत्येक भारतीय मनुष्य के यकृत, वक्ष तथा पुट्ठों के चर्बीयुक्त ऊतकों में १.५ से २ ग्राम तक कीटनाशक रसायन एकत्रित हो जाते हैं, जो 'स्लो पॉइजन' का काम करता है। कुछ लोग मानसिक तनाव में आकर इन दवाइयों का सेवन कर आत्महत्या कर लेते हैं।

कीटनाशक औषधियों के स्थान पर जैविक नियंत्रण का उपयोग किया जाय तो बेहतर होगा, जैविक नियंत्रण में प्राकृतिक शत्रु (परजीवी परभक्षी) का उपयोग किया जाता है, जिससे न तो वातावरण प्रदूषित होता है और न लाभदायक जंतु नष्ट होते हैं तथा आर्थिक दृष्टि से यह एक सस्ती फीट नियंत्रण-विधि है। इसमें कोई छिडकाव एवं भुरकाव यंत्रों की जरूरत नहीं पडती, बल्कि परजीवियों को सीधा खेत में छोड दिया जाता है। परजीवी एवं परभक्षियों, जो विशेष प्रकार के कीट को नष्ट करने में सहायक होते हैं।

परजीवि या परभक्षी का नाम	कीट का नाम	फसल का नाम
१. ट्राइको ग्रामा स्पसीज	तना छेदक	गन्ना
२. टेट्रा सटंकस पाइरिल्लो	प्राइरिल्लो	गन्ना
३. प्लेटीगेस्टर	गंगई	धान
४. रेडूपियड एवं ट्रइको ग्राम	तना छेदक	"
५. केन्थोकोना सीडो मीनास	फाफा	"
६. लेडीवर्ड बीटल	माहो	"
७. मिरिडव हापर	"	"
८. ट्राइको ग्रामा काइलेट्री	चने की इल्ली	चना

१) केन्द्रीय जैविक नियंत्रण अनुसंधान केन्द्र, फरीदाबाद
२) केन्द्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्था, हैदराबाद (आंध्र)
३) जैविक नियंत्रण अनुसंधान केन्द्र, शैलेन्द्रनगर, रायपुर (म. प्र.)
४) केन्द्रीय जैविक नियंत्रण अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर (उडीसा)
४) प्लांट प्रोटेक्स क्वारेन्टाइन स्टेशन, बंबई (महाराष्ट्र)

– आर. एस. कुशवाह

कल की दुनिया शुरुआत करेगी – माताओं से !

हाल्फडान महलर

विश्व-बिरादरी के सामने मौजूद कुछ बुनियादी सवालों में से एक यह भी है कि हम इस धरती के उन निवासियों के लिए एक अच्छा गुणवत्तायुक्त जीवन सुनिश्चित कर पाएंगे या नहीं, जिनकी संख्या इस सदी के अंत तक ६ अरब तथा अगली सदी के अंत तक कोई १० अरब हो जानेवाली है।

हम उस आधी, मूक मानवता अर्थात् भविष्य की माताओं की आकांक्षाओं और आशाओं से कट गए हैं। इन करोड़ों कुपोषित तथा मेहनत से टूटी हुई स्त्रियों और बालिकाओं की आवाज कोई नहीं सुनता तथा उन्हें सत्ता के दायरों से बाहर ही रखा जाता है।

दक्षिण एशिया के गांवों में एक डॉक्टर की हैसियत से मुझे स्त्रियों के जीवन को नजदीक से देखने का मौका मिला है। गरीबी, मशक्कत तथा सतत गर्भधारण के बोझ के नीचे पिसती इन स्त्रियों की हालत खुद बयान करती थी कि इन समाजों में इनकी क्या वकत है। अक्सर, जब भी विकास की कोई योजनाएं बनती हैं, उनमें या तो महिलाओं की स्थिति की उपेक्षा कर दी जाती हैं या "विकसित होती महिलाओं" पर होनेवाली चर्चाओं द्वारा उन्हें हाशिये पर डाल दिया जाता है। लेकिन मेरा विश्वास है कि इस धरती पर कोई भी दूरगामी विकास तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि महिलाओं को उन समाजों की रचना में शामिल नहीं किया जाता, जिनमें हमें रहना है।

अभी तक इस तथ्य को पूरी तरह समझा और मान्य नहीं किया जा सकता है कि परिवार के सारे सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए माता का सेहतमंद होना बहुत आवश्यक है। यह देखकर तो बड़ी तसल्ली मिलती है कि विश्व-बिरादरी हर वर्ष लाखों की तादाद में होनेवाली शिशु-मृत्युओं को लेकर चिंतित है, लेकिन उतना ही बेचैन और भयभीत करनेवाला उसका मौन भी है, जिसके साथ वह प्रसूतिकाओं की मौतों को बर्दाश्त कर रही है।

प्रसव के दौरान होनेवाली मौत आमतौर से जन्म से लेकर अल्पायु में होनेवाली शादी तक भुगते हुए भेदभाव तथा उपेक्षा का चरम बिंदु होती है। यह मौत उन्हीं औरतों को आती हैं, जो भीषण गरीबी में जीती हैं तथा रिवाजों,

हैसियत तथा शिक्षा, स्वास्थ्य-परिचर्या तथा आत्मनिर्णय के अधिकार से वंचित होने के कारण एक सम्पूर्ण व्यक्ति होने का दर्जा कभी प्राप्त ही नहीं कर पातीं। सारा ध्यान शिशु को जिंदा रखने पर केंद्रित कर देने से पूरे परिवार के स्वास्थ्य की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। बगैर मां के स्वास्थ्य व सलामती के, उसके बच्चों के बचे रहने के अवसर भी सीमित हो जाते हैं।

यदि स्त्रियों को स्वस्थ बनाना है तो उनके शिक्षा, प्रशिक्षण, साख, स्वास्थ्य-सुविधा तथा कानूनी संरक्षण उपलब्ध करवाना होगा। गरीब महिलाएं ही शोषण का सबसे ज्यादा शिकार होती हैं। अन्यायपूर्ण श्रम-प्रथाओं, वेश्यावृत्ति तथा शारीरिक हिंसा भी इन्हीं को झेलनी पडती है। पेरु में पुलिस को जिन अपराधों की रपट लिखाई जाती हैं, उनमें से ७० प्रतिशत स्त्रियों को उनके पतियों द्वारा पीटने की ही होती हैं। भारत में वर्ष १९८७ में पुलिस ने दहेज-मृत्युओं के १,७८६ प्रकरण दर्ज किए। लेकिन अहमदाबाद के एक महिला-संगठन का अनुमान है कि एक हजार से ज्यादा बहुएं तो अकेले गुजरात में ही जला दी गई होंगी।

यदि स्त्रियों को इस तरह घरेलू हिंसा और सामाजिक तिरस्कार का शिकार बनाया जाता है तो वे भविष्य की दुनिया को आकार देने में सहभागी कैसे बन सकती हैं? भविष्य की पीढियों को जन्म देने के लिए वे किस तरह सन्नद्ध हो सकती हैं?

हमें महिलाओं को हमारे समाज की मुख्य धारा में लाना होगा और इसकी शुरुआत उनकी स्वास्थ्य-परिचर्या, जिसमें बच्चों को जन्म देने न देने के मामले में उनकी पसंदगी तथा प्रसव-परिचर्या भी शामिल होगी, शिक्षा, साख तथा समाज जो कुछ दे सकता है उसमें बराबरी की भागीदारी, के साथ करनी होगी।

यह सब करने के लिए दस वर्ष पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव को आदर्श मानना होगा जो उसने महिलाओं के विरुद्ध किए जानेवाले सभी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध पारित किया था। यह एक ऐसा व्यापक मानव-अधिकार दस्तावेज है, जिसका यदि सही ढंग से पालन किया जाए तो वह महिलाओं को पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा विश्व-समाज में पूरे अधिकार तथा भागीदारी प्रदान करने की दिशा में एक लम्बी छलांग साबित

गो-सेवा में तन-मन-धन से जुटने का आव्हान
यह 'आह्वान' किसके लिये है?

उसके लिये नहीं– जो केवल 'गोमाता की जय' बोल कर सन्तुष्ट रहना चाहता हो।

उसके लिये अवश्य है – जिसके चित्त में गोमाता के लिये कुछ न कर पाने के कारण छटपटाहट हो, कुछ न कुछ करने की अकुलाहट हो–भारत में गाय-बैल की दुर्दशा देख-सुन कर जिसे तडपन होती हो, जिसकी बेचैनी छलकी पडती हो–जो भारत को केवल भूखण्ड नहीं, अपितु विशिष्ट सांस्कृतिक चेतना का पुञ्ज समझता हो।

उसके लिये भी है – जिसे गोरक्षा की बात में दकियानूसीपन की गन्ध आती हो–

इस आह्वान को सुन लिया हो तो आइये, अपना-अपना कर्तव्य-मार्ग हम अपने-अपने स्वधर्म के अनुसार तय करें, और इस प्रक्रिया में जिस हृदय-मन्थन में से गुजरना अनिवार्य हो, उसके लिए तैयार रहें!

हो सकता है। यह घोषणा-पत्र सरकारों को महिलाओं को अधिकारों तथा दर्जा प्रदान करने के मामले में कानूनी मार्गदर्शन देता है। लेकिन कानूनी उपायों का औचित्य तभी सिद्ध होता है, जबकि उनका परिपालक ठीक से हो तथा स्त्रियों के प्रति पुरुषों के रवैये में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हों।

महिलाओं का दर्जा वास्तविक तथा कानूनी रूप से बढाना विकास, प्राकृतिक संसाधन, प्रबंधन तथा भविष्य की पीढियों के कल्याण की दृष्टि से सबसे अहम सरोकार है। हमारी धरती की सुरक्षा से संबंधित समस्याओं के हल काफी हद तक हमारे अपने भीतर ही मौजूद हैं और वे इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम एक-दूसरे के बारे में अपनी धारणाओं, पूर्वाग्रहों तथा आचरणों को किस हद तक बदल पाते हैं।

(सप्रेस, पेनोस, पर्यावरण कक्ष एवं गांधी शांति केंद्र के सहयोग से)

* *

यदि हम–

१. शिक्षक या विद्यार्थी हैं तो मानव-जीवन में श्रम का स्थान, श्रम में नर-बल के साथ पशु-बल का सहयोग और मानव की बुद्धि-मेधा के संवर्धन में गोदुग्ध का स्थान समझायें।

२. माता-पिता हैं तो अपनी सन्तान को ताजा गोदुग्ध, छेना, छेना व दूध की मिठाई का ही सेवन करायें और उनमें गोमाता के प्रति कृतज्ञता का भाव-बीज बोयें। बाजारू कृत्रिम पोषक द्रव्यों का उपयोग यथासम्भव न करें।

३. चिकित्सक हैं तो गोवंश की चिकित्सा में परम्परा प्राप्त नुस्खों, औषधियों, जडी-बूटियों की खोज करें और मानव-स्वास्थ्य की रक्षा में गोदुग्ध, गोमूत्र आदि की महिमा उजागर करें।

४. अर्थ-शास्त्री हैं तो श्रम-केन्द्रित अर्थ-व्यवथा में गाय-बैल का स्थान समझें, समझायें। पूंजी-केन्द्रित अर्थव्यवस्था को सर्वग्रासी बनने से रोकने के उपाय सोचें। गोवंश के प्रति समग्र दृष्टि विकसित करें, जिसमें दुग्ध, खाद, जलावन, जोत और ढुलाई को यथोचित स्थान हो। इस दृष्टि के अनुसार गाय-बैल के जीवन के अन्तिम क्षण तक अनुपयोगी नहीं होते– इस सत्य को प्रतिष्ठित करें।

५. कृषि-शास्त्री हैं तो सेन्द्रिय खाद को रासायनिक खाद की तुलना में वरीयता कैसे मिलें, इसके उगाय सोचें। विषाक्त रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर गोमूत्र के प्रयोग पर अनुसन्धान करें, करायें।

६. व्यवसायी या उद्योगपति हैं तो गोमांस, गोचर्म आदि के व्यापार और निर्यात को बन्द करने-कराने का उद्यम करें, और उद्योग में गाय की खाद्य-वस्तुओं का (अन्य वस्तु बनाने में) उपयोग न बढे, इसका ध्यान रखें।

७. कृषक हैं तो गोसेवा को कृषि का अभिन्न अंग बनाये रखें। बैल को हटा कर 'ट्रैक्टर' आदि न लायें।

८. वकील या कानून के ज्ञाता हैं तो गोरक्षा-सम्बन्धी कानूनों का पालन कराने के लिये निःशुल्क पैरवी करें, या सलाह दें और गाय के स्थूल-सूक्ष्म रूपों का, उनके पोषक निहित स्वार्थों का पर्दाफाश करें।

९. न्यायाधीश हैं तो गोरक्षा-सम्बन्धी कानूनों के छिद्रों की आड में जोर पकडती गोहत्या का प्रतिकार करें।

१०. नीति-निर्धारक हैं तो भारतीय समाज में गाय के केन्द्रीय स्थान को समझ कर तदनुसार आर्थिक, औद्योगिक, शैक्षणिक, निर्यात-सम्बन्धी नीति बनायें।

११. धर्माचार्य-सन्त-महन्त हैं तो मठों-मन्दिरों में गोदुग्ध-गोघृत के ही उपयोग का नियम बनायें।

१२. चिन्तक-विचारक हैं तो मानव-जीवन के 'संस्कार' में गोवंश के साथ प्रेममय सम्बन्ध के मर्म को प्रकट करें।

१३. पत्रकार हैं तो गोरक्षा के प्रयत्नों के समर्थन और गोवंश-नाश के दुश्चक्र के विरोध के लिए जनमत तैयार करने के उद्देश्य से तत्सम्बन्धी समाचारों को प्राथमिकता दें।

१४. कवि या लेखक हैं तो गोवंश की मूक वेदना को वाणी दें, जिससे पत्थर पिघलें और उपेक्षा-उदासीनता के स्थान पर करुणा-संवेदनशीलता जागे।

१५. पुलिस अधिकारी या कर्मचारी हैं तो गोरक्षा के कानूनों को तोडनेवालों को पकडने तथा दण्डित कराने में सहयोग करें। चोरी-छिपे गोवध, अवैध लदाई और राज्यान्तरण इत्यादि को रोकें।

१६. कतलखाने के अधिकारी या कर्मचारी हैं तो कानून के छिद्रों की आड में गोवध को बढावा देने का और स्वस्थ गाय-बैलों को भी 'अनुपयोगी' करार देने का घोर पाप करते हुए यह न समझें कि आप प्रत्यक्ष गोहत्या नहीं कर रहे हैं।

१७. मांसाहारी हैं तो कम से कम मानव-जीवन के लिए सर्वाधिक उपयोगी पशु-गोवंश (किसी भी आयु व स्थिति के गाय-बछडा बछिया-बैल-साँड) का मांस वर्जित रखें।

१८. सामान्य नागरिक हैं तो – (१) अपने घर में निकलनेवाले सब्जी, फल के छिलकों, भूसी, चोकर आदि को अलग रखें, कूडे में न मिलायें – यह सामग्री किसी गाय का ग्रास बने, इसका उपाय करें।

(२) सुविधा हो तो एक गाय अवश्य पालें।

(३) गोदुग्ध को भैंस-दूध के समान दाम दें। दोनों की तुलना सूक्ष्म गुणवत्ता से करें, न कि ऊपरी गाढे-पतलेपन से या 'फैट' की कमी-बेशी से।

(४) नगरों में प्रत्येक बस्ती में ताजा गोदुग्ध सुलभ हो सके, इसके लिए गोशालाओं की स्थापना के लिए आवाज उठायें।

(५) गोवंश का महत्व केवल 'हिंदू' के लिए नहीं, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए है, इस सत्य को समझें-समझायें।

भागलपुर :

जहां इन्सान मारा गया, इन्सानियत जिंदा है

गत साल बिहार के भागलपुर नगर और अगल-बगल के २०० गांवों में भीषण दंगे हुए, जिसमें १००० हिंदू और मुसलमान मारे गए और कई हजार घायल हुए। भागलपुर के उस अशांत सांप्रदायिक वातावरण में बहुत से मुसलमान भाई मिले, जिन्होंने दंगों के समय बहुत से हिंदुओं को अपने घरों में छुपा के रखा, बहुत से हिंदू भाइयों की रक्षा अपने परिवार में रखकर की, यह कोई मामूली काम नहीं था। दंगे के संबंध में केवल एक बात का उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि अवतारों, पैगंबरों, संत-महात्माओं और महापुरुषों के विचारों को आधार बनाकर समाज के इतने टुकडे कर दिये गए हैं कि पूर्णता का भाव मन में नहीं रह गया है, जिसके फलस्वरूप जीवन और समाज के कण-कण में हिंसा बारूद बनकर व्याप्त हैं, जो मामूली चिंगारी के द्वारा ज्वाला बनकर भस्मीभूत कर देती है। छोटे-छोटे घरौंदों में अपने आप को मनुष्य ने बांधकर 'समाज' संज्ञा को निरर्थक बना दिया है। इस भीषण दंगे को एक साल उलट जाने के बाद अभी भी वहां हिंदू-मुसलमान समाज में परस्पर मिलना-जुलना बंद था और फिर से दंगा होने का डर बना था। यह देखकर अभी हाल में ही देश के विभिन्न हिस्सों के पंद्रह-बीस सर्वोदय के कुछ

---

(६) 'हिन्दुहिं मधुर न देहिं, कटुक तरुकनि न त्रियार्वाहिं' – इस ऐतिहासिक वाक्य का सतत स्मरण करें।

(७) गोसेवा, गोरक्षा के प्रयत्नों में यथाशक्ति आर्थिक सहायता दें।

(८) हम सबके हाथ किस प्रकार परोक्ष रूप से गाय के रक्त में सने हैं इसे समझें और स्वीकारें।

हम सब

जागें! .....सोचें! .....समझें! .....बोलें! .....करें!

('आचार्यकुल', अगस्त ९० से साभार)

– डा. प्रेमलता शर्मा

* *

प्रबुद्ध सेवक और शांति-सैनिक भागलपुर में इकट्ठा हुए थे। बिहार तथा भागलपुर के लोगों को मिलाकर ५० लोगों की ५ टोलियां बनाई गई थी, और एक सप्ताह में पांच ब्लाकों में सघन रूप से घूमकर लोगों के घावों पर मरहम लगाने का काम इन टोलियों ने किया। अनुभव आया कि लोग यह महसूस करने लगे हैं कि हिंदू-मुसलमान आदि नाम तो कहने के लिए हैं, वस्तुतः इंसान मारा गया है। कई पीढियों से एकसाथ रहने वाले लोगों में जो विश्वास की आधार-शिला थी, वह चकनाचूर हो गई।

भागलपुर में अब तक जो प्रयास किये गये उसमें कुछ नाम उल्लेखनीय हैं। सर्वश्री आचार्य राममूर्ति, शिवानंद भाई, डा. रामजी सिंह और भागलपुर जिला खादी-ग्रामोद्योग सघ के मंत्री सुरेंद्र बाबू शांति और सद्भावना के लिए लोगों का अभिक्रम जगाने में अग्रगण्य रहे हैं। प्रो. ठाकुरदास बंग, एस. एन. सुब्बाराव, गोपीनाथ नायर, यशपाल मित्तल, स्वामी सत्यभक्तजी की सेवाएं शांति-स्थापना के कार्य में बहुत मूल्यवान सिद्ध हुई हैं। भागलपुर का शांति प्रतिष्ठान केंद्र तथा उससे संबंधित लोगों ने तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। श्री सुब्बाराव के मार्गदर्शन में देशभर से आये हुए ६०० नवयुवकों का का एक शिविर एक सप्ताह तक तातारपुर मुस्लिम हाईस्कूल में चलाया गया। प्रतिदिन शाम को जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को निर्भय बनाने का कार्य संपादित हुआ। उसके बाद आचार्य राममूर्ति के मार्गदर्शन में लगभग २०० हिंदू-मुसलमान भाइयों का दो दिनों का शिविर बहुत उत्साहवर्धक रहा। लेकिन अभी जुलाई के अंतिम सप्ताह में जो पांच टोलियों के माध्यम से अभियान चलाया गया उस पर से आवश्यकता महसूस हो रही है कि कम से कम छः माह तक सतत दिलों को जोडने का काम किया जाए।

एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति सहज ही पैदा हो गई कि पुलिस पर से लोगों का विश्वास बिलकुल उठ गया। प्रशासन के लिए चुनौती है और अपनी कर्तव्य-परायणता सिद्ध करने के लिए उसे चाहिए कि लोग उस पर भरोसा कर सकें। अपने जान-माल का रक्षक और जनता के सेवक के रूप में उसे देख सकें। सभी दुनिया अनुभव से महसूस करने लगी है कि मानव में अपने संहार का इतना साधन जुटा लिया है कि सिवाय गांधीजी के रास्ते के उसे त्राण मिलने वाला नहीं है। तो क्यों न हम इस विनाश-लीला से बाहर निकल कर एक-दूसरे के जीवन में शरीक हों, उत्सवों और रीति-रिवाजों में भागीदार बनें, ताकि किसी अफवाह

मालेगांव गोरक्षा आंदोलन

कानून की हत्या रोकने के लिये एक कदम आगे

१९८२ से महाराष्ट्र में नासिक जिले के मालेगांव परिसर में गोरक्षा आंदोलन जारी है। १९८४ में इंदिराजी गांधी अपने प्रधान मंत्री-काल में जब आयी थीं, तब गोरक्षा-बंदी कानून को बार-बार तोडे जाने की बात कार्यकर्ताओं ने उनके सामने रखी, तब उस समय साथ में पधारे हुए तत्कालिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री वसंतराव दादा पाटील से उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कानून है, उसका पालन होना चाहिए। लेकिन शासन के रवैये में तब भी कोई परिवर्तन नहीं आया है और ईद आदि त्यौहारों पर नवजवान बछडे काटे जाने का सिलसिला जारी है। कानून का सहारा लेकर उसको रोकने की कोशिश कार्यकर्ता करते हैं तब कानून तोडनेवालों को सजा देने के बजाय कार्यकर्ताओं को डराने-धमकाने का काम पुलिस द्वारा आज भी होता है।

इस साल नागरिकों ने, विशेषतया वेपारी परिवार की बहनों और पढी-लिखी युवतियों ने और साथ-साथ अडोस-पडोस की किसान-महिलाओं ने कतल के लिये लाये गये पशुओं को प्रमाणित करनेवाले व्हेटर्नरी डॉक्टरों के कार्यालयों के सामने निदर्शन किया और बछडे कतल के लिये लाये जा रहे थे तब उन्हें रोकने की कोशिश की, तब कार्यकर्ताओं को ही डराने की कोशिश की गई। उस समय श्रीमती जमनाबहन कुटमुटिया उपोषण के लिये बैठ गईं। पांच दिन यह उपोषण चला। मालेगांव नगर की वेपारी महिलाओं ने भी ८०० की संख्या में शासन के रवैये के खिलाफ और गोवंश बचाने के लिये एक दिन का उपवास किया।

का शिकार न होना पडे। सर्वधर्म सद्भाव तक गांधीजी ने हम सबको पहुंचाया था। अब अगला कदम एकमात्र मानव-धर्म की ओर बढना चाहिए, ताकि विज्ञान के द्वारा समाप्त हुई दूरियों का लाभ लेकर विश्व-परिवार को सार्थक बनाया जा सके। (सप्रेस)

— रामप्रवेश शास्त्री

❋ ❋

आठवीं योजना और पर्यावरण संरक्षण

सुन्दरलाल बहुगुणा

गत २५ जून को योजना आयोग ने देश के विभिन्न भागों में पर्यावरण की रक्षा के लिये कार्यरत लगभग दो दर्जन सक्रिय आंदोलनकारियों और वैज्ञानिकों को परामर्श के लिये बुलाया। इसमें केरल शास्त्र साहित्य परिषद के प्रो. एम. के. प्रसाद, गोवा के पत्रकार क्लाड अल्वारिस, 'नर्मदा बचाओ' आंदोलन की मेधा पाटकर, अरावली बचाओ आंदोलन के किशोर संत, विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र के अनिल अग्रवाल, कल्पवृक्ष के आशिष कोठारी, भारतीय विदेश सेवा के अवकाशप्राप्त अधिकारी सुनील कुमार राय, त्रिवेन्द्रम के धरती विज्ञान केन्द्र के निर्देशक डा. सुव्रत सिन्हा आदि मुख्य थे। योजना आयोग की ओर से प्रो. रजनी कोठारी, लक्ष्मी चन्द्र जैन, जे. डी. सेठी, अरुण बोस, टी. एन. शेषन और सलाहकार प्रो. शेखर सिह तथा श्रीमती बडठाकुर मुख्य थे। पर्यावरण मन्त्री राउत राय और राज्य मन्त्री श्रीमती मेनका गांधी तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री रामकृष्ण हेगडे दिल्ली से बाहर होने के कारण इसमें शामिल नहीं हो सके।

आयोग द्वारा चर्चा के लिये तैयार किये गए आधार-पत्र में मानव जाति समक्ष तापमान बढने, ओजोन की छतरी में छेद, वन-बिनाश, हवा, मिट्टी और

बंबई से श्री अच्युतकाका आये। कृषि-गोसेवा संघ के महामंत्री श्री केशरी-चंद मेहता ने जिला एस. पी. पुलिस-अधिकारियों से परिस्थिति को संभालने के लिये सलाह-मशविरा किया।

गत साल भर में ५४३६ बैलों की कुरबानी दी गई थी। इस साल इस निदर्शन के कारण कुरबानी के लिये आये सैंकडों बैल-बछडे रास्ते ही से वापिस हुए।

कुरबानी और कानून, ये दो परस्पर-विरोधी बाते हैं। फिर भी हर साल कलेक्टर, एस. पी. इस समस्या को टालते हैं और पशु वैद्यकीय अधिकारियों के सामने पुलिस की देखरेख में हजारों गोवंश काटा जाता है। इस अवैध, असंवैधानिक गोवंश-कतल को और कानून की कतल को रोकने का दृढ संकल्प यहां के कार्यकर्ताओं ने किया है। * *

पानी के प्रदूषण और इनके फलस्वरूप मानव त्रासदी और चिन्ता का जिक्र किया गया था । इस परिप्रेक्ष्य में यह स्वीकार किया गया था कि संसाधनों के केन्द्रीकरण और उस पर राज्य के स्वामित्व के कारण सामन्त लोगों के जीवन के आधार प्राकृतिक संसाधन उनकी पहुंच के बाहर हो गये हैं । इनका उपयोग नगरों के विलासितापूर्ण जीवन की आवश्यकताओं पूर्ति के लिये की हो रहा है । अत: आज सरकार के सामने इस प्रक्रिया को उलटाना पहली चुनौती है जिससे बढती हुई जनसंख्या की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार हो सके कि उसका भावी पीढियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

भारत का पर्यावरण –

भारत के पर्यावरण की परिस्थिति को चर्चा करते हुए इस पत्र में कहा गया कि औद्योगिक काष्ठ का वार्षिक आयोग २ करोड ८० लाख घनमीटर है, लेकिन वनों की वार्षिक वृद्धि केवल १ करोड २० लाख घनमीटर मात्र है। शेष की पूर्ति वनों से पुन: उत्पादन क्षमता से अधिक लेकर ह्रास किया जा रहा है। पशुओं के लिये ९३ करोड २० लाख टन हरा और ७८ करोड टन सूखा चारा प्रतिवर्ष चाहिये । इसमें केवल २५ करोड टन हरा और ४१ करोड ४० लाख टन सूखा चारा ही उपलब्ध है । शेष की पूर्ति बनों में चराई से होती है। जलाऊ लकडी की खपत २३ करोड ५० लाख घनमीटर वार्षिक है, जबकि वार्षिक उत्पादन ९ करोड टन ही हैं। विश्व में भारत में प्रतिव्यक्ति सबसे कम ०.११ हेक्टेअर वनक्षेत्र हैं। थाईलण्ड में ०.५० हे० है। लेकिन थाईलण्ड ने पिछले वर्ष से वनों की व्यापारिक कटाई पर पाबन्दी लगा दी है। भारत में यह जोरों से जारी है ।

प्रतिवर्ष ६०० करोड टन उपजाऊ मिट्टी बहकर समुद्र में चली जाती है। इसमें ५० लाख टन उर्वरक भी नष्ट हो जाते हैं । इनका मूल्य २५०० करोड रुपये हैं। भारत की एक-तिहाई भूमि (१० करोड हे० से अधिक) भूक्षरण, लवणीकरण और दलदलीपन से ग्रस्त है। तीन-चोथाई किसानों के पास प्रति परिवार २ हे० से कम असिंचित भूमि है, जो स्वावलम्बन की दृष्टि से अपर्याप्त है । बांध-जलाशयों में उपेक्षिता से गाद भर रही हैं, जिससे उनकी आयु कम हो रही है। १९६० के बाद बाढ प्रभावित क्षेत्र १ करोड ९० लाख हे० से बढकर ५ करोड ९० लाख हे० (तिगुना) हो गया। सन १९८३ और १९८६ के बीच भारत के आधे से अधिक जिले बाढ और सूखे के प्रकोप से पीडित रहे हैं।

सत्तर प्रतिशत से अधिक सतही जल प्रदूषित है और बडी-बडी नदियों के बहुत बड़े क्षेत्र का पानी पीने के योग्य तो दूर की बात रही, नहाने के योग्य भी नही रह गया है !

भारतीय नगर वायु-प्रदूषण की दृष्टि से विश्व में सबसे अधिक प्रदूषण वाले नगरों की श्रेणी में आते है। कोई भी बडा भारतीय नगर रासायनिक और आण्विक प्रदूषण के प्रकोप से मुक्त नहीं। दिल्ली और बम्बई में १००० से अधिक प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों का पता चला।

देहाती क्षेत्रों में करोडों लोगों के लिये जिन्दा रहने मात्र के लिये पानी-ईंधन-चारा और दूसरा कच्चा माल प्राप्त करने में कठिनाइयां निरन्तर बढती जा रही है।

पर्यावरण की रक्षा के लिये प्राथमिकताएं –

साधारण पत्र में चार मुख्य प्राथमिकताएं दी गयी हैं। इसमें सर्वाधिक प्राथमिकता लोगों की अपने जिन्दा रहने के लिये आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों तक न्यायपूर्ण और निरंतर पहुंच को दी गयी है। दूसरी प्राथमिकता प्राकृतिक संसाधनों के सरकारी नियंत्रण के विकेंद्रीकरण की सुझाई गयी है, जिससे लोगों के लिये अपने ही संसाधनों के बेगाना हो जाने की मोजूदा लहर की दिशा को मोडा जा सके। तीसरी प्राथमिकता अन्यायपूर्ण और निरन्तर कायम न रहने वाले विकास के ढांचे में परिवर्तन की हो। इसमें संसाधनों की फिजूल खर्ची और उपभोग निहीत है। चौथी प्राथमिकता प्रकृति को बचाने और पुनर्जीवित करने के लिये समन्वित सरकारी प्रय सों की आवश्यकता की है।

व्यवहार और आदर्श की दूरियां –

जहां तक इस आधार-पत्र में की गई स्वीकारोक्तियां और सुझाव हैं इसमें कोई सन्देह नहीं कि ये पर्यावरण की चित्ता करने वालों का बहुत हद तक समाधान कर सकती है। लेकिन सभी क्षेत्रों में हमारी मुख्य समस्या तो आदर्श और व्यवहार की दूरी है। हमारी सरकारें और उनका संचालन करने वाले राजनेता आदर्शों के गगन में विहार करते हैं, लेकिन कदम पर वे व्यवहार के पाताल में धडाम से गिरते हुए देखे जाते हैं। बनों की तबाही पर घडियाली आंसू तो सबही बहाते हैं, लेकिन शायद ही भारत का कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो जिसने वन-संरक्षण अधिनियम को समाप्त करने या लचीला बनाने की मांग न की हो। वोट-प्राप्ति की होड के इस कानून के लागू होने

के बाद नदी-घाटी परियोजनाओं के लिये आनन-फानन में दी गई स्वीकृतियों की बात तो छोड दीजिये, केवल और म. प्र. में राजनैतिक नेताओं के प्रोत्साहन पर जंगल काटकर वनभूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण के ऐसे उदाहरण हैं, जहां भूमि का क्षेत्रफल सैकडों नहीं हजारो हे. हैं। निजी पेडों को काटने की स्वीकृति देने में कई बनमंत्री आपस में होड कर रहे हैं! हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में हजारों खर के पेडों की कटाई कें मामले को दबाया जा रहा है तो जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में हरे पेडों की कटाई केवल इसलिये चालू कराई गई थी कि एक केंद्रिय नेता के ठेकदार पिता को वन विभाग की ओर से ठेके मिल सकें।

भारत का वन-प्रवन्ध व्यापार और पुलिस-प्रवन्ध के दो पापग्रहों से ग्रस्त हैं। अंग्रेजों ने उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में अपने व्यापारिक हितों जहाज और रेलवे लाइनें बिछाने के लिये वनों को ग्राम समुदायों से छीन कर अपने हाथों में ले लिया था। इन सरकारी वनों को सुरक्षित (रिजर्व) बन की संज्ञा दी गयी। सरकार के हाथों में वनों के आ जाने से उनके प्रबन्ध में नगरों के वाहुल्य वाले समाज की विलासिता की वस्तुओं ओर व्यापारिक कच्चे माल के उत्पादन को प्राथमिकता दी गई। उधर जनसंख्या की वृद्धि के कारण खेती के लिये भी वनों का विनाश हुआ।

कृषि-प्रधान भारत को ही नहीं, सभी देशों के लिये यह आवश्यक है। कि वे अपनी बुनियादी पूंजियों जल, जमीन और जंगल – की सुरक्षा की चिन्ता करें। सतत विकास का आधार ये ही हो सकते हैं, न कि धातु और खनिज सम्पदायें, जिनके ऊपर आज की भोगवादी सभ्यता टीकी हुई है। भले ही समुद्र की गहराइयों से हम खनिज तेल निकालकर मालामाल वन जावें, लेकिन तेल से सागर को प्रदूषित करके वहां से बनने वाले बादल तो समाप्त हो गये, वर्षा कम हो गई। अब तो हमारे पास वर्षा लाने वाला समुद्र केवल बंगाल की खाडी ही है। अवश्य ही कृत्रिम ऊर्जा से भूमिगत जल को खींचकर अंगूर और गन्ना पैदा किया जा सकता है, लेकिन कितने समय तक? क्योंकि पुनः संचालित न हो सकने के कारण भूमिगत जल का स्तर तेजी से गिरता जा रहा है।

जल-उपयोग के सम्बन्ध में एक बुनियादी सवाल यह है कि क्या भागीरथी का पानी ३०० कि. मी. दूर दिल्ली पहुंचाने और केवल ६ घंटे

प्रतिदिन २४०० मेगावाट विजली देने के लिये ४२ वर्ग कि. मी. धरती को डुबाकर अधिक से अधिक सौ वर्ष जीने वाला टिहरी बांध बनाया जावे या भागीरथी के पानी को केवल ३ से ३०० मीटर ऊपर उठा कर पहाडों की हरियाली को सघन वृक्षारोपण के द्वारा लौटाया जावें। इससे लोगों को घर-द्वार छोडकर विस्थापित करने के बजाय अपने ही परिवेश में समृद्ध बनाया जा सकेगा, नदी के प्रवाह को अधिक नियमित किया जा सकेगा, जिससे सीधे प्रवाह से विद्युत-उत्पादन की क्षमता बढेगी, इंधन के लिये लकडी मिलेगी। ये दोनों निरंतर उपलब्ध होने वाली नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत हैं।

इतिहास साक्षी है कि जमीन के दुरुपयोग से किस तरह बडे-बडे साम्राज्य ध्वस्त हो गये। दुनिया के गरीब देश आज विदेशी मुद्रा कमाने को होड में अपनी भूमि का उपयोग उन चीजों को पैदा करने के लिए कर रहे हैं, जो अधिक मुद्रा ला सके। यह मिट्टी के उपजाऊपन का निर्यात है। भूमि का पहला उपयोग स्वयं मिट्टी और पानी के संरक्षण के लिए इस प्रकार करना चाहिये, जिससे प्राणवायु, पानी, खाद्य आवास और वस्तू की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति आसपास के क्षेत्र से हो सके हरित क्रांति में अपनाई गई रासायनिक खाद, बीज, कीटनाशक और पानी की मदद से पैदावार में बृद्धि करने के सपने पूरी दुनिया में चकनाचूर हो गये हैं। सन् १९५० से १९८४ के बीच अन्न के उत्पादन में २.६ गुना वृद्धि हुई थी, लेकिन सन् १९८९ में सन् १९८४ के मुकाबले केवल एक प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। बढती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति संचित भण्डारों को खाली करके हुई और फिर भी कुछ लोग भूखमरी के शिकार हुए !

योजना आयोग की बैठक में साठ वर्ष पूर्व गांधीजी द्वारा अर्थशास्त्री डॉ. जे. सी. कुमारप्पा से ग्राम नियोजन के लिये कराये गये खेडा (गुजरात) के मातर तालुका के आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोट भी विपरीत की गई। इससे ऐस लगा कि क्या योजना आयोग पिछली सात योजनाओं की असफलताओं के बाद अब गांधी की याद करने लगा है ? गांधी की यह विशेषता थी की वह जटिल समस्याओं के सरल समाधान प्रस्तुत करता था, जिसे हर कोई अपना सके। भूमि-उपयोग के सिद्धांत को वे सबसे अधिक प्राथमिकता देते थे। इसीलिये उन्होंने सन् १९२६ में वृक्ष खेती का सुझाव दिया था. क्योंकि इसके लिए कम मेहनत और कम पानी चाहिये। अब तो वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इससे अन्न की खेती के मुकाबले पांच से दस गुनी अधिक पैदावार होगी। पकाने के लिये ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। भूक्षरण, लवणीकरण और दलदलपन

की समस्यायें स्वत: ही हल हो जावेंगी। गांधी एक कदम आगे गये थे। वृक्षों की पैदवार का आहार सात्विक होगा और लोगों की प्रवृत्ति अहिंसा की ओर होगी। आज की परिस्थिति में भारत की करोडों हेक्टेयर भूमि के क्षय और पानी की निरंतर बढती हुई कमी को रोकने का इसके सिवाय और कोई दूसरा उपाय नहीं।

भारत को सही विकास नीति की ओर बढने में सबसे बडी रुकावट पिछले ४० वर्षों से चली आ रही उद्योग और ऊर्जा की नीतियां है। आज राजनैतिक और सीमित मात्रा में आर्थिक क्षेत्र में विकेन्द्रीकरण की बातें तो होती हैं, लेकिन भारत के भाग्यविधाता राजनेताओं को सामान्य लोगों की व्यवहार बुद्धि (विजडम) पर कम भरोसा है। इसके विपरीत गांधी को उस पर अटूट श्रद्धा थी। यह कहा जाता है कि ये अनपढ-गंवार लोग गलतियां कर सब कुछ गुड-गोबर कर देंगे, इसलिए उनके हाथों में बडे अधिकार देना खतरे से खाली नहीं। ठीक है, वे स्कूल-अस्पताल, सडकें देख लें। पर लक्ष्मीचन्द जैन मानते हैं कि गांव-स्तर पर गलत निणय होंगे तो एक ही गांव पर उसका असर पडेगा, पर जब केन्द्र-स्तर पर गलत निर्णय होते हैं तो उसका असर तो सारे देश पर पडेगा। करोडों को भुगतना पडेगा।

औद्योगीकरण के लिए अंधश्रद्धा ने बहुराष्ट्रीय और बडी-बडी राष्ट्रीय कंपनियों को भारत के गरीब लोगों के सिर पर बिठा दिया हैं। वे जोक की तरह संसाधनों और लोगों की कमाई का शोषण कर रही हैं। गांव के उद्योग उजड गये हैं। घर-घर में बाजार घुस गया है। केन्द्रीय उत्पादन पद्धतियाँ अनुत्पादक लोगों — मैनेजर, बैंकर, ब्रोकर (दलाल), विज्ञापनकर्त्ता और भार-वाहकों की एक फौज खडी करते हैं, जिसका बोझ प्रकृत और गरीब श्रमिकों-उत्पादकों व उपभोक्ताओं पर पडता है। जब तक अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुओं का विकेंद्रित उत्पादन नहीं होता, न तो शोषण से ही और न प्रदूषण से मुक्ति मिल सकती है। सबको रोजगार देना तो दूर का सपना रह जावेगा।

केन्द्रीय उत्पादन-पद्धति के साथ ही केंद्रित ऊर्जा भी जुडी हुई है। भारत जैसे जनसंख्याप्रधान देश में ऊर्जा की प्राथमिकताएं आज भी परमाणु ताप व बडे बांध बनाकर जल विद्युत प्राप्त करने के विपरीत मानव, पशु बायोगैस, सौर, पवन, समुद्री लहर, तप्त तल और समुद्र के प्रवाह से जलविद्युत होनी चाहिये। उत्पादन बढाने और काम का ऊबाऊपन कम करने की क्षमता रखने वाले ऐसे यंत्रों का आविष्कार व विकास होना चाहिये, जिनमें उपरोक्त ऊर्जास्रोतों का उपयोग हो सके।

दूध-उत्पादन का महत्वपूर्ण आधार भैंस नहीं, गाय है

— शरदचन्द्र भटोरे

अगस्त ९० को 'भास्कर' में भाई श्री विनोद तिवारी ने भैंस पर अपने विचार प्रस्तुत किये है ओर लिखा है कि—

(१) भैंस का शक्तिशाली होना ओर गहरे कीचड में आसानी से चलने की क्षमता के कारण यह पशु यातायात का अच्छा साधन बन गई है। यद्यपि इसमें चलने की गति बहुत धीमी है।

(२) घास-चारे की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाय, तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के मजबूत आधार हो सकते हैं।

भैंस की तारीफ करना अच्छा ही है। किन्तु जो पशु दूध में, शक्ति में, स्फूर्ति में, सेन्द्रिय खाद में, गोमूत्र, कीटनाशक का विकल्प बन रहा है, इस अर्थ में जो पशु अत्यधिक उपयोगी है, उस गाय का, गोमाता का उल्लेख न करना पाठकों के साथ अन्याय है।

कुछ वर्ष पूर्व करनाल के शोध-संस्थान में भैंस व गाय के दूध पर तुलनात्मक अध्ययन हुआ है। एक वर्ष के बाद जो नतीजा सामने आया, उसने बताया कि गाय से छह हजार रुपये का अधिक मुनाफा हुआ है।

भैंस यदि वास्तव में शक्तिशाली है ओर यातायात का अच्छा साधन बन गई है तो किसान बैलगाडी का उपयोग न करके भैंस-गाडी, का उपयोग क्यों नहीं करते ? और इन्दोर शहर में पचासों रणगाडे स्टेशन मे और विभिन्न बाजारों से माल ढोने का काम करते हैं, उसमें इंदोर के नागरिकों ने तो एक भी भैंस-गाडी के दर्शन नहीं किये हैं।

माता के दूध के बाद गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ है, यह बात डाक्टरों ने बताई है ओर इसलिये कि वह जल्दी पच जाता है। भैंस-दूध में अधिक फेट तत्व होने से वह जल्दी पचता नहीं है और इसीलिये वह हानिकर भी है। ४ प्रतिशत से अधिक फेट को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हानिकर बताया है।

दूध का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है। भैंस-मुर्रा भैंस १०-१२ लीटर दूध देती है, जो संख्या में कम ही है। किन्तु गाय—देशी गाय—गीर नस्ल की गाय

गोरक्षा-सत्याग्रह-समर्थन-अभियान

निवेदन

प्रिय मित्र,

आपको विदित ही है कि पूज्य विनोबाजी के आदेश से ११ जनवरी १९८२ से वंबई स्थित देवनार कतलखाने पर देशभर के लिए गोहत्यावंदी का केंद्रीय कानून बनाने के उद्देश्य से सत्याग्रह चल रहा है। यह सत्याग्रव असांप्रदायिक, अराजनैतिक और अहिंसक है।

सत्याग्रह को प्रभावी वनाने के उद्देश्य से देश के प्रमुख साथियों की एक संगोष्ठी का आयोजन १ तथा २ अगस्त १९९० को पवनार में किया गया था। इस संगोष्ठी में सर्वसम्मति से यह निर्णय किया गया कि आगामी ५ माहों में देश के लाखों लोगों का सत्याग्रह को सक्रिय समर्थन प्राप्त हो, इसके लिए एक अभियान ही चलाया जाये। अपेक्षा यह है कि इस अभियान में हम लोग शीघ्रातिशीघ्र कम-से-कम एक करोड लोगों तक पहुचें, उन्हें सत्याग्रह का संदेश दें और उनसे सत्याग्रह के समर्थनस्वरूप एक-एक रुपया प्राप्त करें।

कम-से-कम समय में अधिक-से-अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। अत: निम्नानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(१) इस अभियान का शुभारंभ विनोबा-जयन्ती, ११ सितम्बर १९९० से किया जा रहा है।

२५-३० लीटर दूध देती है। इस वास्तविकता को बहुत थोडे लोग जानते हैं। और यही कारण है कि दुनिया के उन्नत राष्ट्र गाय के दूध का उपयोग करते हैं और भैंस रखते ही नहीं।

गाय का दूध बल, वुद्धि और स्फूर्ति प्रदान करता है। खिलाडियों और और विद्यार्थियों को सिर्फ गाय के दूध का ही उपयोग करना चाहिए।

गाय कामधेनु है। भारतीय अर्थ-व्यवस्था का मूलाधार गाय है।

गाय कितनी उपयोगी है, इस पर इंदौर में दीपावली के बाद एक परिसंवाद आयोजित किया जायेगा। महाविद्यालयों में साहित्य उपलब्ध होगा। पुरस्कार भी रखे गये हैं। विद्यार्थियों को इसका लाभ लेना चाहिये।

* *

(२) अभियान का केंद्रीय कार्यालय, पवनार आश्रम, वर्धा (महाराष्ट्र) – ४४२१११ में रहेगा। (फोन : ३५७७)

(३) अभियान के प्रचार-पत्रक तथा समर्थन-पत्र केंद्रीय कार्यालय से भेजे जायेंगे। आवश्यक होने पर प्रांतीय भाषाओं मे भी वैसे ही पत्रक और समर्थन-पत्र छपाये जा सकते हैं।

(४) समर्थन-राशि का ५०% अंश केंद्रीय कार्य के लिए केंद्रीय कार्यालय में भेजा जाए।

(५) शेष ५० % राशि सत्याग्रह संबधी कार्य तथा प्रवास, पोस्टेज, प्रचार-पत्रक, गोरक्षा-साहित्य-प्रचार के हेतु क्षेत्रीय-विनियोग के लिए रहेगी।

(६) ग्राम, मोहल्ले तथा नगर के सत्याग्रह-समर्थकों को सम्मिलित कर स्थानीय समिति का गठन किया जायें और सत्याग्रह शिविर, घाटकोपर, बंबई द्वारा प्रकाशित "शांति सेवक" पाक्षिक का प्रचार तथा सामूहिक वाचन बैठकों में किया जाय। और सूचनानुसार कदम उठाने के लिए सदस्य तत्पर रहें।

(७) सत्याग्रह के लिए जन-समर्थन प्राप्त करना ही इस अभियान का उद्देश्य है।

इसलिए गोरक्षा के संबंध में साहित्य-प्रचार शिबिर, पदयात्रा, गोष्ठियां, सम्मेलन आदि आयोजित करने चाहिए।

इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए लिखिए या मिलिए—

संयोजक

पवनार आश्रम, वर्धा (महाराष्ट्र) गोरक्षा-सत्याग्रह समर्थन अभियान

* *

गांधी शांति प्रतिष्ठान कार्यकर्ता सम्मेलन में गांधी की चुनौती अभियान में भाग लेने का निर्णय

गांधी शांति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली का कार्यकर्ता-सम्मेलन गत २१ व २२ अगस्त को नई दिल्ली में संम्पन्न हुआ। नई दिल्ली और देश के ग्यारह राज्यों से आये हुए छत्तीस प्रतिनिधि सम्मिलित हुए।

इस वर्ष का सम्मेलन ऐतिहासिक है और नए अध्याय का आरंभ करता है। इस संस्था के संस्थापक-अध्यक्ष श्री आर. आर दिवाकरजी १९५० से इस

संस्था को अंतर्राष्ट्रीय गौरव-गरिमा प्रदान करने के बाद अध्यक्ष-पद से निवृत्त हुए तथा थोड़े समय बाद उन्होंने देह त्याग दिया। यह पहला मौका था, जब सम्मेलन उनके प्रबोधन से वंचित रहा। इसी वर्ष अपनी बीस वर्ष की सेवा के बाद श्री राधाकृष्णजी के जैसे योग्य मंत्री आग्रह पूर्वक पदमुक्त हुए। सम्मेलन के नए अध्यक्ष श्री रवींद्र वर्मा तथा मंत्री श्री एन. कृष्णास्वामी संस्था से वर्षों से जुडे रहे, इस कारण परिवर्तन ने सहजता से नयापन प्रदान किया।

नया अध्याय मुख्य रूप से इसलिए माना जाएगा कि गत वर्ष संस्था ने "शांति-सद्भावना" का व्यापक लोक-शिक्षण के अभियान का आरंभ किया। इसकी सफलता तथा लोक-आकांक्षाओं के कारण, इस वर्ष गांधी की चुनौती" का देशव्यापी अभियान खडा करने में सफलता पायी।

सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए अध्यक्ष श्री रवींद्र वर्मा ने कहा कि गत वर्ष सेवाग्राम में हमने "शांति सद्भावना" का कार्यक्रम उठाया था और आज एक साल बाद दुनियां की स्थिति अधिक विस्फोटक और हिंसक हो गई है। सारी दुनिया में अहिंसा और सहअस्तित्व के नए समीकरण की खोज हो रही है। साथ ही हिंसा और अशांति की भयंकरता से सारा संसार प्रकम्पित हो रहा है। इस गहन संकट में गांधी की अनिवार्यता और भी अधिक तीव्रता से महसूस की जा रही है। कालचक्र की तेज गति हमें "नाऊ ऑर नेव्हर" का संकेत दे रही है, इस कारण हमारा आगे का एकमात्र कार्यक्रम होगा – "गांधी की चुनौती"। इस काम को देश की रचनात्मक संस्थाओं ने सराहा है, सहयोग के लिए आगे आ रही हैं, इसलिए यह अब मात्र गांधी स्मारक निधि, सर्व सेवा संघ, कस्तूरबा ट्रस्ट और गांधी शांति प्रतिष्ठान का ही कार्यक्रम नहीं, देश के रचनात्मक संस्थाओं का कार्यक्रम बन गया है। गांधी शांति प्रतिष्ठान के आजीवन सदस्य तथा सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष श्री गोपीनाथन् नायर ने इसके देशव्यापी संयोजन का अनुभव बताते हुए कहा कि गत चार माह में मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है कि "गांधी की चुनौती" का कार्यक्रम अपेक्षा का प्रतीक बन गया है। इससे स्पष्ट आसार दीख रहा है कि "गांधी की चुनौती का अभियान" संस्थाओं का कार्यक्रम नहीं, एक लोक-अभियान के रूप में देश को दिशा दे सकेगा।

इस वर्ष का सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा कि प्रतिनिधियों ने देश के राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति श्री वेंकट रमण ने, जो संस्था के

कस्तूरबाग्राम कृषि-क्षेत्र द्वारा
कार्यशाला का आयोजन

कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट, कस्तूरबाग्राम, इंदौर द्वारा संचालित कृषिक्षेत्र द्वारा म. प्र. विज्ञान एवं तकनीकी परिषद और आवास-विकास वित्त निगम के वित्तीय सहयोग से आगामी २ अक्टूबर से १२ अक्टूबर तक मानव-उत्सर्जित मल-मूत्र के पुनर्उपयोग पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।

अरविंद आश्रम, पांडिचेरी के श्री चिमनलाल गुप्ता, ग्रामीण पुनर्रचना एवं विकास संस्थान, नई दिल्ली के श्री जे. बी. सिंह, डा. एन. वी. मजूमदार, सुलभ इंटरनेशनल नई दिल्ली, डा. व्ही. आर. जोगलेकर, शिवसदन गृह निर्माण सहकारी समिति सांगली तथा डा. एस. व्ही. मापुसकर, जोत्स्ना आरोग्य प्रबोधन, पुणे मुख्य प्रवक्ता एवं मार्गदर्शक होंगे।

दो चरणों में चलनेवाली इस कार्यशाला में इंजीनियर, ठेकेदार; स्वायत्त-शासी संस्थाओं तथा संगठनों के प्रमुख, स्वास्थ्य एवं सफाई निरीक्षक, सामाजिक

अध्यक्ष और मंत्री के चिर-परिचित तथा शांति-प्रतिष्ठान के कार्यों से अवगत रहे, इनसे मिलकर हार्दिक प्रसन्नता प्रगट की। वे जागतिक परिस्थिति और देश के संकट का स्मरण करते हुए अपने स्वातंत्र्य संग्राम के बीते दिनों की याद कर भावाविभोर हो गए। उन्होंने कहा, दुनियां को गांधी के अतिरिक्त और दूसरा विकल्प नहीं है। राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि आजादी की लडाई में खादी हमें प्रेरणा देती थी, आज भी खादी और ग्रामोद्योग में हर हाथ को काम देने की अपरिमेय शक्ति है। लोकतंत्र और विकेन्द्रीयकरण के अतिरिक्त दुनियां के लिए शांति का दूसरा रास्ता नहीं है।

सभी प्रतिनिधियों ने एक स्वर से संकल्पबद्ध निर्णय लिया कि हम अपनी जिम्मेवारियों और आवश्यक अपेक्षित कार्यक्रम का निर्वाह करते हुए "गांधी की चुनोती" कार्यक्रम के लिए प्राण-प्रण से समर्पित रहेंगे। सम्मेलन ने निर्णय लिया कि आगामी २ से ११ नवंबर तक गांधी की गूंज भारत के एक लाख गांवों में ले जाने के इस कार्यक्रम में हमें लोक-शक्ति का विराट दर्शन होगा तथा विश्वास है कि लोक-गंगा हमारे जीवन और आंस्थाओं को दिव्यता प्रदान करेगी। ☆

वनस्पति में निकिल खानेवालों की मुश्किल

वनस्पति घी की जांच करने पर, उसमें निकिल धातु की उपस्थिति पायी गई। इस आशय का एक समाचार प्रेस ट्रस्ट ने १ जुलाई १९९० को लखनऊ से प्रेषित किया था। यह एक चौंका देने वाला समाचार था। अपने देश में वनस्पति की काफी मात्रा में खपत है। उसमें निकिल की उपस्थिति स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यधिक हानिकारक है। आशा थी कि समाचार देश के करोड़ों उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से संबंधित होने के कारण अत्यधिक गंभीरता से लिया जायेगा। परंतु हम अंतिम क्षण तक किसी भी विषय को गंभीरता से नहीं लेते हैं, वह विवाद चाहे आसाम से संबंधित हो, या फिर पंजाब, या कश्मीर से। जब राष्ट्रीय महत्व के इन प्रकरणों को हमने नासूर बनने की सीमा तक पनपने दिया, तब जनता के स्वास्थ्य से संबंधित विवाद तो तुलना में बहुत ही साधारण है।

चार प्रमुख वनस्पति-निर्माताओं के नमूनों का परीक्षण, लखनऊ की पर्यावरण संशोधन प्रयोगशाला ने कर निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक ४० ग्राम वनस्पति की मात्रा में १ ग्राम निकिल की मात्रा उपस्थित है। प्रयोगशाला के

कार्यकर्त्ता तथा पर्यवेक्षक भाग लेंगे। इस अवसर पर शौचालय आधारित दो या तीन प्रकार के बायोगैस संयंत्रों का निर्माण किया जाएगा, जिसका उपयोग परिवार और समाज के लिए हो सकेगा। इससे प्राप्त उत्तम खाद से भूमि की उर्वरा शक्ति बढाने तथा जनजीवन के लिए प्रदूषणमुक्त पर्यावरण में मदद मिलेगी। इसके अलावा शौचालयों के विभिन्न माडलों की एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। भारत में खेतों के लिए गोबर और गोमूत्र उर्वरक हैं। परंतु गोबर के उपलों का उपयोग जलावन में करने से इसकी कमी महसूस की जा रही है। दस दिवसीय इस कार्यशाला में संबंधित अनेक प्रश्नों एवं उपायों पर विचार किया जाएगा। यह जानकारी कृषि के निदेशक श्री गोविंद कुट्टी मेनन ने दी है।

* *

कार्यकारी निर्देशक डा. एम. सी. सक्सेना का हस्ताक्षरयुक्त प्रकाशित वह रिपोर्ट चिंताजनक है। जस्ते की तरह विषैली यह धातु नित्य के भोजन के साथ उपभोक्ताओं के पेट में एकत्रित हो रही है। वर्ष अनुवर्ष निकिल की यह मात्रा जो वनस्पति में लगभग २.५ प्रतिशत है, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर किस प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, यह आनेवाला समय ही बतायेगा। चिंता की बात यह है कि आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि माध्यमों पर कुपोषण से बचने के विज्ञापन बहुतायात में प्रचारित होने के बाद भी, इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया गया।

कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली में एक सर्वेक्षण किया गया था। जिसमें डी. डी. टी. नाम के विषैले पदार्थ की काफी मात्रा लोगों के पेट में मौजूद है, यह निष्कर्ष निकला था। इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उदाहरण एकत्र किये हैं कि भारतवर्ष में हृदय रोग, मधुमेह तथा रक्तचाप आदि रोगों के बढते प्रमाण के पीछे, डी. डी. टी. नामक विष का पेट में जाना है। अब सोने में सुहागा, डी. डी. टी. के साथ उसका मित्र निकिल भी आ गया है। डी. डी. टी. नामक विषैले कीटनाशक रसायन का प्रयोग, किसान अपनी फसलों की कीटों से रक्षा करने में करते है। अतः यह रसायन अनाज, फल, सब्जी आदि के माध्यम से पेट में पहुंचता है। इससे बचने के लिये उपभोक्ताओं को इन पदार्थों का प्रयोग अच्छी तरह धोकर, करना चाहिए।

वनस्पति-निर्माता निकिल का प्रयोग तेलों का हाइड्रोजनीकरण करने में उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। तेलों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा ही वनस्पति तैयार होता है। उत्प्रेरक के रूप में प्रस्तुत निकिल के अवयव किस प्रकार वनस्पति में स्थानांतरित होते हैं, इन्हें किस प्रकार स्थानांतरित होने से रोका जाये, यह महत्वपूर्ण प्रश्न वनस्पति-निर्माताओं तथा सरकार दोनों के लिये विचारणीय है। यदि वनस्पति निकिल से मुक्त नहीं होता तो उसे प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है।

वनस्पति से संबंधित सरकारी नीति अत्यधिक उदार है। इसके निर्माण हेतु सरकार ने अन्यान्य तेलों को किसी भी अनुपात में मिश्रित करने की अनुमति प्रदान कर रखी है। जिन तेलों का वनस्पति के निर्माण में उपयोग किया जाता है। उपभोक्ता उन तेलों में से किसीका भी सीधे रूप में उपयोग नहीं करते।

यह तेल सेलम, सोयावीन, आयातिति रेपसीड, पाम, विनौला, सूरजमुखी, महुआ, करडी, राइस ब्रान, नाइगर सीड, तरबूज के बीज, सेस सोड फेट, पामोलिन तथा मेज तेल आदि हैं।

वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति तैयार किया जाता है, जिससे इसका क्वथनांक (बाइलिंग पाइंट) बढता है। उपभोक्ता वर्णित तेलों का विरंजन तथा गंधविहीन करने आदि की प्रक्रियाओं के पश्चात इन तेलों के हाइड्रोजनीकरण करके सफेद, दानेदार घी की तरह पदार्थ अर्थात वनस्पति तैयार होता है

क्वथनांक बढने से इसे पचाने के लिये शा रीर को अधिक उर्जा की आवश्यकता होती है। अत: वनस्पति की मात्रा अपाच्य रह जाती है, जिससे पेट में जलन, खुजली, गैस आदि विकारों का जन्म होता है। वहुत से लोगों को एलर्जी भी होती है। कोलस्ट्राल की मात्रा तो निश्चित रूप से बढती है, क्योंकि मूल तेल का पाचक तत्व लिनोलिक एसिड हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में नष्ट हो जाता है, अत: संतृप्त वसीय अमल की मात्रा बढती है, जो हृदय रोग रक्तचाप, असंतुलन आदि रोगों का उत्तरदायी है। इन सबके साथ अव निकिल की मात्रा भी शरीर में प्रवेश करने लगी है, अत: सहज ही स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है।

बीमारियों का कष्ट तथा खर्च सहन करने से अच्छा तो इस प्रकार के उत्पादनों का बहिष्कार करना है। सरकार से हम मात्र अनुरोध करने की स्थिति में हैं कि वह जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड करने वालों से कडाई से निपटें, यह उसका दायित्व है। अधिक लोग अस्वस्थ होंगे तो अंतत: सरकार के स्वास्थ्य विभाग पर खर्च एवं कार्य का दबाव आयेगा। जव तक यह सिद्ध न हो कि वनस्पति निकिल या अन्य हानिकारक अवयवों से रहित है, इसका बहिष्कार करना ही श्रेयस्कर है।

एम्प्रेस मिल चाल नं. २१/८,
सुभाष रोड, नागपुर

रागिनी त्रिवेदी

(२७ अगस्त के 'नवभारत' दैनिक से साभार)

* *

गोशालाओं को कृषि-गोसेवा का शिक्षण-केंद्र बनायें

दिसंबर में राष्ट्रीय गोशाला संगोष्ठी

वाराणसी की रामेश्वर गोशाला और आचार्यकुल के सहयोग से दिनांक २१ से २३ दिसंवर, १९९० को गोशलाओं और गोसेवकों का सम्मेलन रामेश्वर गोशाला वाराणसी में रखना तय हुआ है।

दिसंवर में वाराणसी में सर्दी वहुत रहेगी। इसलिए साथ में आवश्यक ओढना-विछौना लावें। श्री रामेश्वर गोशाला वाराणसी शहर से पचीस किलोमीटर दूरी पर काशी की पंचक्रोशी-यात्रा के तीसरे पडाव पर है। वहां जाने के लिए वाराणसी से वसों की व्यवस्था रहेगी।

रामेश्वर गोशाला संस्था का परिचय भाई श्री शरदकुमार साधक के नीचे दिये गये लेख से होगा।

राधाकृष्ण बजाज

गोपुरी, वर्धा — अध्यक्ष, अ. भा. कृषि-गोसेवा संघ

* * *

देश में लगभग २५०० गोशालाएं हैं। वे आधुनिक संदर्भ में कैसे उपयोगी हो सकती हैं, इसके बारे में सोचने का समय आ गया है। केवल दया-दान के भरोसे चलने के कारण जो गोशालाएं उपयोगी हो सकती हैं, वे जन-उपेक्षा की शिकार हो गयी हैं। उन्हें गोरक्षा आन्दोलन के साथ जोड देने से न केवल वे कृषि-गोसेवा का शिक्षण-केन्द्र वन जायेंगी, वरन् उसमें दुग्ध क्रांति एवं हरित क्रांति से भी ठोस धरती मिलेगी।

पिछले ५ वर्षों से श्री काशी जीवदया विस्तारिणी गोशाला एवं पशुशाला गोरक्षा आन्दोलन से जुडी, तव उसके रामेश्वर केन्द्र में निम्न परिणाम आये :—

१) पांच वर्षों में कतल के लिए जानेवाला लगभग ४० हजार गोवंश बचा।

२) कसाइयों के हाथों से छुडाया गया गोवंश जरूरतमंद किसानों में वितरित किया गया, जिससे गरीबी मिटाने में मदद मिली।

३) जिन गाय-बैलों को किसानों ने भी लेना स्वीकार नहीं किया, उन्हें गोशाला ने संरक्षित, संबर्धित कर उपयोगी बनाया, जिससे गोशाला एक ऊर्जा-केन्द्र बन रही है।

४) गो-मूत्र एवं गोबर से न केवल गोबर-गैस बन रही है, वरन् उसीसे बनी सेन्द्रिय खाद तथा गोमूत्र के छिडकाव से कृषि सुधरी है और रासायनिक खाद का व्यवहार करनेवाले किसानों का रुख बदला है।

५) गाय-बैलों के रहने से उसर, बंजर भूमि उपजाऊ बनी है।

६) जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए जगह-जगह छोटे, कच्चे बांध बनाने से लोगों को एक वर्ष में पांच हजार श्रम-दिनों का काम मिला और जल-संग्रह होने से क्षेत्रीय जलस्तर ऊपर उठा है।

गोपालन के साथ-साथ अनेक सहयोगी उद्योग लग रहे हैं।

वाराणसी की इस गोशाला की उपलब्धियों के आधार पर हम विश्वास के साथ यह कहने के स्थिति में हैं कि–

१) गोशालाएं अपनी गोचरभूमि का सही उपभोग कर नवजीवन पा सकती है।

२) गोशाला से नसल-सुधार एवं पशु-पालन के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक दाखिल हो सकती है। देशी नसल को सुधारने में यहां विशेष प्रयोग हो सकते हैं।

३) गोसदन के रूप में गोशालाएं विकसित होकर डेयरियों का विकल्प बन सकती हैं।

४) गोशालाएं अपने आपमें समग्र ग्रामविकास का शिक्षण-केंद्र बन सकती हैं, क्योंकि उनके पास जमीन, साधन और अन्य अनुकूल ताएं हैं।

गोशालाओं की उपलब्धियों का परस्पर परिचय कराने के लिए अ. भा. कृषि गोसेवा संघ को चाहिए कि वह एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करें।

– शरदकुमार साधक
दुर्गाकुंड, वाराणसी (उ. प्र.)
संपादक – 'आचार्यकुल'

स्व. श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट को श्रद्धांजलि

'धर्मों की फुलवारी' के लेखक, भूदान-यज्ञ और विनोबा-प्रवचन के संपादक तथा सर्व सेवा संघ प्रकाशन के एक स्तंभ श्री श्रीकृष्णदत्त भट्ट ने ता. ४ अगस्त १९९० को काशी में अपना भौतिक देह छोडा। उनका स्वभाव शांत, सरल, सख्यमय और सात्विक था। उन्होंने अपनी जीवन-यात्रा, साहित्यिक प्रतिभा और हृदयस्पर्शी लेखनी से अनेकों को प्रेरित किया था। 'गीता प्रवचन' के हिंदी अनुवाद में अनेक सुझाव पू. विनोबाजी ने मान्य रखे थे। आचार्य दादा धर्माधिकारी ने सर्वोदय-दर्शन में संशोधन का उन्हें अधिकार दिया था।

उनका जन्म पौष शुक्ला १४ संवत् १९७० में कैथावा, जिला – इटावा (उ. प्र.) में हुआ। उन्होंने साधनों के अभाव में अपने सही स्वभाव को पहचाना और साहस से पुरुषार्थ में लग गये। स्वाश्रयिता और स्वावलंबन से उन्होंने अपने आपको शिक्षित किया और हिंदी में तथा समाजशास्त्र में एम. ए. तक की पढाई की। वे एक अच्छे पत्रकार थे। उन्होंने 'अधिकार', 'आज', 'समाज', 'लोकवाणी', 'राष्ट्रवाणी,' 'नवशक्ति' आदि पत्रों का संपादन किया और भारत की जनता में आजादी की भावना फैलाने और चेतना जगाने का निर्भयतापूर्वक कार्य किया। देश की आजादी के आंदोलन में वे सक्रियता से जुड गये। इसके लिए उन्हें सन् १९३२-३३ में जेल-यात्रा करनी पडी और सन् १९४१-४२ में नजरबंदी में रहना पडा।

आजादी के बाद वे सर्वोदय आंदोलन में जुड गये। सर्वोदय विचार-प्रचार, साहित्य-निर्माण और संपादन के काम में बडी तन्मयता से जुड गये।

ग्रामदान के संदर्भ में 'चलो चलें मगरौठ' और चंबल घाटी के डाकुओं के समर्पण के संदर्भ में 'चंबल के बेहडों में' आदि सर्वोदय आंदोलन की पुस्तकों ने काफी लोगों को प्रेरित किया। सर्वधर्म समन्वय की दृष्टि से उनके द्वारा लिखी गयी 'धर्मों की फुलवारी' बडी प्रसिद्ध हुई और बंगाल हिंदी मंडल, उत्तर प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार द्वारा भी वह पुरस्कृत हुई। इसके अतिरिक्त 'भारतवर्ष का आर्थिक इतिहास, भारतवर्ष का सांस्कृतिक इतिहास,' आर्थिक विचारधारा : उदय से सर्वोदय तक, 'सामाजिक विघटन और भारत' तथा

सत्साहित्य की करीब ७० से अधिक रचनाएं उनकी प्रकाशित हुई हैं। कई पुस्तकें काशी विद्यापीठ, भागलपुर विश्वविद्यालय आदि में बी. ए., एम. ए. के पाठ्यक्रम में भी हैं।

श्री भट्टजी स्वतंत्रता सेनानी, सर्वोदय के अनन्य सेवक और सरस्वती के उपासक थे। उनका जीवन धर्ममय था। इसीलिए काशी के विश्वधर्म शांति संमेलन (डब्लू. सी. आर. पी.) ने उन्हें अपना अध्यक्ष बनाया था। उनके भौतिक शरीर के वियोग के लिए सर्वोदय-परिवार उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता है!

साधना केन्द्र, राजघाट,
वाराणसी – १

कृष्णराज मेहता

★ ★

गांधीवादियों का एक अध्ययन दल दक्षिण अफ्रीका रवाना

दक्षिण अफ्रीका में डरबन शहर के निकट गांधीजी का फिनिक्स आश्रम था। कुछ वर्ष पहले जातीय दंगों में वह आश्रम जल गया था। अभी वहां के लोगों की इच्छा है कि उस आश्रम को पुनर्जीवित किया जाए तथा भारत-अफ्रीका मैत्री के प्रतीक के तौर पर उसे विकसित किया जाए। स्थानीय प्रयत्नों में भारत व दुनिया के गांधी-प्रेमियों का सहयोग मिलें, ऐसी अपेक्षा रखी गई है। भारत सरकार ने स्थिति का अध्ययन कर आवश्यक सिफारिश करने की दृष्टि से एक दल दो सप्ताह के लिए वहां भेजने का तय किया है। अध्ययन दल में सेवाग्राम आश्रम के मंत्री श्री कनकमल गांधी, गांधीग्राम विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा. डी. के. ओझा तथा केरल के मित्र निकेतन आश्रम के श्री विश्वनाथन सम्मिलित हैं। यह दल गत २४ अगस्त को दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गया।

नेल्सन मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने हाल ही में घोषणा की है कि वे हिंसा का मार्ग छोडकर अहिंसक मार्ग से अपनी समस्याएं हल करेंगे। श्री मंडेला स्वयं अक्टूबर ९० में भारत आ रहे हैं। उस समय सेवाग्राम भी आएंगे ऐसी आशा है।

❋ ❋

इस्तोनिया : स्वतंत्रता के साथ हरियाली की चाह

वेलो पोहला

इस्तोनिया पूरब और पश्चिम की सीमा पर स्थित यूरोप के सबसे टिकाऊ बसाहट वाले देशों में से है। इस्तोनियाईवासी अपने इलाके में कम से कम ५००० वर्षों से रह रहे हैं। आज लगभग १५ लाख की आबादी में ६० प्रतिशत इस्तोनियाई लोग हैं, जबकि सन् १९४४ में इनकी संख्या ९४ प्रतिशत थी। चूंकि ये लोग कृषकों के वंशज हैं, अतः एक तरह से प्रकृति का हिस्सा हैं।

सन् १९४० में सोवियत सैनिकों ने इस्तोनिया पर हमला कर उसे अपने साम्राज्य में शरीक कर लिया। आज रूस के कई राष्ट्र एक नई जागृति की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। उनका राष्ट्रवाद कोई स्वार्थ पर आधारित अलगाववाद नहीं है। ये राष्ट्र (या राज्य) वास्तव में स्व-निर्णय, मातृभाषा के संरक्षण तथा अपने प्राकृतिक संसाधनों को फिर से प्राप्त करने और अपने उत्पादों के स्वामित्व को बहाल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

लगभग पचास वर्षों के अंतराल के बाद मार्च, १९९० में इस्तोनियाई संसद के लिए स्वतंत्र चुनाव हुए। सोवियत संघ के रूस सहित सारे राष्ट्र इसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। रूस का इतिहास देश के सारे इलाकों के उग्र-उपनिवेशीकरण का रहा है, जिसमें सारे केंद्रीय मंत्रालयों की भूमिका विशाल बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरह रही है। इसीका नतीजा यह हुआ है कि सम्पूर्ण सोवियत संघ पारिस्थितिकी संकट की कगार पर पहुंच गया है। देश के विशाल क्षेत्रफल के बीस प्रतिशत हिस्सों को संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है।

इस्तोनिया के जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वे कृषि-प्रदूषण से प्रभावित हैं। कृत्रिम उर्वरकों तथा रासायनिक शाकनाशियों के कारण मिट्टी की उपजाऊ और खादयुक्त परतें नष्ट हुई हैं। दुर्भाग्यवश बड़े सामुदायिक तथा सरकारी स्वामित्व के फार्मों ने भूमि को जोतने के जैव-तरीकों को पूरी तरह उपेक्षा की जिसकी वजह से इस्तोनिया की आधे से ज्यादा मिट्टी तथा भू-जल क्षतिग्रस्त हो गया है। उपयोग किया हुआ या उत्सर्जित पानी उस बाल्टिक सागर में बहा दिया जाता है तो पहले ही कृषि और औद्योगिक प्रदूषण का शिकार है। किसी जमाने में प्रख्यात, इस्तोनिया के समुद्र-तटों में से अधिकांश को नहाने-धोने के लिए बंद कर दिया गया है। ❋ ❋

देवरिया और बस्ती जिले में गोरक्षा अभियान

श्री. योगिराज देवराहा बाबा सेवा समिति द्वारा संचालित गोरक्षा अभियान बडे सफलतापूर्वक चल रहा है। पूज्य सद्गुरु श्री. देवराहा बाबाजी महाराज के गोलोक-धाम हो जाने के बाद अवश्य अपूरणीय क्षति हुई है। फिर श्री बाबाजी के आशीर्वाद, श्री बजाजजी के निर्देश एवं शुभचिंतकों के आशीर्वाद से हम लोगों का मनोबल बना हुआ है।

गत २६ जुलाई' ९० को २५ बैलों को थानाध्यक्ष बघौच धार देवरिया के श्री लालजी पांडेय ने गोरक्षकों की सूचना पर ६ व्यापारियों सहित राष्ट्रीय राजमार्ग से गोवध हेतु बिहार ले जाते समय गिरफ्तार कर अपराध सं. ८३६/९० धारा ५A/८ उ. प्र. गोवध अधिनियम एक्ट ए. ११ पशुक्रूरता के तहत जिला जेल भेज दिया। साथ ही बरामद बैलों को थाने के परिसर में जिला सक्षम अधिकारी के आदेश के प्रतिक्षा में भरण-पोषण कर रहे हैं। गिरफ्तार व्यापारियों का सरगना जावेद, हुसैन पुत्र रामबलि मिश्र सा. नेवादा, परसौनी थाना उच्चका, जि. गोपालगंज बिहार का रहनेवाला है, जो पुराना पशु-तस्कर हैं। उसने स्वीकार किया कि मैं बराबर पशुओं को वध हेतु बंगाल कमीशन एजेंट के रूप में भेजता हूं।

दिनांक १४ अगस्त को थाना दुधारा, जि. बस्ती के उपनिरीक्षक कमलाकांत मिश्र ने ग्राम नब्बा गांव के पास पी. डब्ल्यू. डी. चौराहे पर १९ पशुओं सहित ३ कसाइयों को गिरफ्तार कर गोवध एक्ट के तहत चालान कर दिया, जिनमें २ अभियुक्त ग्राम उचरहा, थाना-दुधारा तथा एक कोतवाली खलीलाबाद का निवासी है।

श्री योगिराज देवरहा बाबा सेवा समिति के सदस्य पूर्वांचल के गोवंश तस्करी वाले प्रमुख मार्गों पर कडी निगरानी कर रहे हैं।

विजय शंकर पांडेय
विशेष सचिव
श्री योगिराज देवरहा बाबा राष्ट्रीय सेवा समिति,
पत्रकार निवास, लाररोड,
देवरिया (उ. प्र.)

सेवाग्राम में आचार्यकुल परिषद

समाज के सामने उपस्थित समस्याओं का सम्यक अध्ययन करके तटस्थ भाव से समाज को समुचित मार्गदर्शन करने के लिये शिक्षा-जगत को शासनमुक्त स्वायत्तता दिलाने के लिये विनोबाजी ने आचार्यकुल की स्थापना की स्व. श्री. श्रीमन्नारायण, बाद में श्री. रा. कृ. पाटील इस कुल के अध्यक्ष बने। अब श्री. बालविजयजी इसके अध्यक्ष हैं।

अध्यक्ष महोदय के बुलाने पर ता ११ से १३ सितंबर ९० तक आचार्यकुल की प्रथम बैठक पवनार में और बाद की चार बैठकें सेवाग्राम में हुई। इस गोष्ठी में १४ छोटे टिप्पण विविध विषयों पर लिखे गये, तो जानकारी के लिये दिये गये।

इस गोष्ठी में राष्ट्रीय एकात्मता, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र का विकास, प्रशासनिक सुधार, राष्ट्रीय समस्याओं के संदर्भ में परस्पर विचार-विनिमय से आम राष्ट्रीय राय बनाने की पद्धति आदि विषयों पर चर्चा हुई और इस संबंध में सात प्रस्ताव पारित किये गये।

यह संगोष्ठी अपने आपमें राष्ट्रीय एकात्मता का प्रतिक बन गई थी। इसमें कन्याकुमारी के कॅथालिक धर्मगुरु थे (जिन्होंने तीन बार भारत के साथ वफादार रहने की घोषणा की) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहमंत्री श्री. सुदर्शनजी थे, शीख युवक भी था। दक्षिण भारत कोचीन के जॉन सच्चिदानंद थे, तो कलकत्ते के व्यापारी श्रावगीजी भी थे। श्री. राधाकृष्ण बजाज जैसे ८६ साल के बुजुर्ग थे, वैसे ही ३०-३५ साल का जवान सत्यप्रकाश भरत भी था। सर्वश्री रा. कृ. पाटील, बाबूभाई पटेल और बलवंतसिहजी जैसे एक जमाने के नेक मंत्री-प्रशासक थे, तो बंगजी, रणजित् भाई जैसे सेवक भी थे। श्रीमती अन्नपूर्णा बहन, मदालसा बहन, प्रमिलाबहन, विजया वेले जैसी विदुषी बहनें थी, संस्कृत के पंडित डॉ. वर्णेकर थे। श्री चंद्रशेखर धर्माधिकारी और श्री देशपांडे जैसे हायकोर्ट के न्यायाधीश भी आये थे। इसके अलावा और कइयों ने विचारदान में मदद दी।

इस गोष्ठी का संचालन आचार्यकुल के मंत्री श्री नरेंद्रभाई ने किया। नौ प्रस्ताव पारित किये गये। उसमें एकात्मता, आरक्षणं, कृषि-औद्योगिक संरचना आदि प्रस्ताव महत्व के हैं। अगले अंक में हम उनका सार प्रस्तुत करेंगे।

जाती, धर्म, भाषा, प्रदेश, विचार-प्रणालियां कार्यक्षेत्र विभिन्न रहते हुए भी तीन दिन तक बडी तत्परता से विचारों का आदान-प्रदान चलता रहा, जिससे परस्पर को समझने में बडी मदद मिली।

रजि नं. WDA 86 विना टिकट भेजने का परवाना नं. 8
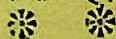
सुप्रीम कोर्ट द्वारा
औरंगाबाद कोर्ट का फैसला रोका गया

अ. भा. कृषि-गोसेवा संघ के महामंत्री श्री. केशरीचंदजी की ओर से खबर मिली है कि औरंगावाद हायकोर्ट ने पकडी हुई गायों को वापस लौटाने एवं निलाम करने का ऑर्डर दे दिया था। पंद्रह दिन का समय दिया था। ऑर्डर की नकलें भी समय पर नहीं मिली। फिर भी प्रयास करके सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। खुशी की वात है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल हो गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने 'स्टे ऑर्डर' दे दिया, फैसला रोक दिया है।

प्रिन्टेड मैटर

प्रेषक : 'गोग्रास', गोपुरी – ४४२११४, जिला वर्धा (महाराष्ट्र)